04 - महाराष्ट्र में क्यों कारगर नहीं हुआ संविधान बचाने का नारा

05 - जन-जन के सम्मान का प्रतीक हमारा संविधान

06 - पहली बार संभागीय स्तर पर आयोजित होगी रीजनल इंडस्ट्रियल...

07- प्रकृति प्रदत्त वाणी एवं मनुष्य कृत भाषा

A Daily News Magazine

भोपाल

बुधवार, 27 नवंबर, 2024

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-88 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

प्रसंगवश

महाराष्ट्र व झारखंड विस चुनाव नतीजों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा

उमेश चतुर्वेदी

हर राज्य की अपनी अहमियत है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी राज्य का है तो वह महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी इसी राज्य में है। मराठी मानुष ने जो जनादेश दिया है, उसका असर देश की राजनीति पर तो पड़ेगा ही, अर्थनीति पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी कई बदलाव नजर आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की अगुआई राहुल गांधी से छीनने को लेकर आवाज उठने लगी है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मांग आ भी गई है कि मोदी को चुनौती देने के लिए जरूरी है कि इंडिया गठबंधन की कमान राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को दी जाय।

महाराष्ट्र के क्षत्रप शरद पवार को लेकर हाल ही में कहा जाने लगा था कि उनके बिना महाराष्ट्र की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। इस धारणा को ढाई साल पहले बीजेपी ने तोड़ दिया था। एकनाथ शिंदे की अगुआई में शिवसेना में टूट हुई और सबसे ज्यादा 104 विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता देवेंद्र फडनवीस को शिंदे का सहयोगी बनने के लिए राजी कर लिया। इस सरकार के कार्यकाल में हुआ लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुआई वाली महायुति को समर्थन नहीं मिला। बीजेपी और शिवसेना-शिंदे- दोनों को लोकसभा सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इससे बीजेपी और शिवसेना दोनों ने सीख ली। बीजेपी ने अपने पारंपरिक गढ़ विदर्भ पर फोकस तो किया ही, गैर मराठा वोटरों पर भी अपना ध्यान लगाया। मराठवाड़ा में शिवसेना शिंदे और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया। नतीजा सामने है। पार्टी ने इस बीच एक काम और किया। उसने माझी लाडकी बहीण योजना लागू की। इसके तहत 21 से 65 साल तक की उम्र वाली पात्र महिलाओं को 1500 रू. महीने दिए जाने लगे हैं। राज्य की करीब 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने लगा है। इसका फायदा महाराष्ट्र की महायुति सरकार को हुआ है। हालांकि झारखंड में एनडीए का यह फॉर्मूला नहीं चल पाया है।

महाराष्ट्र के चुनावों का असर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ सकता है। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में 13 सीटें जीतकर बड़ा दल बनने के बाद कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे में पार्टी खुद को सबसे आगे रखने और सहयोगी दलों को पीछे रखने की रणनीति पर काम करने लगी। चुनाव नतीजे आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह खींचतान सामने आई, उससे साफ था कि कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं था। इसका असर चुनाव नतीजों पर साफ नजर आ रहा है। इसकी तुलना में झारखंड में पार्टी ने हेमंत की सहयोगी की भूमिका में रखा तो वहां के नतीजे अलग तरीके से आए। महाराष्ट्र के नतीजों से दिल्ली में कुछ महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी उत्साह में होगी। कांग्रेस जहां उसके साथ जाने का दबाव बना सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी कुछ और मुफ्तिया वादों के साथ मैदान में मजबूती से उतर सकती है।

महाराष्ट्र के चुनावों में असली उत्तराधिकारी कौन का सवाल भी हावी था। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों खेमे, सभी खुद को ही असली शिवसेना और असली एनसीपी बता रहे थे। इस चुनाव में बेशक अजित पवार के खेमे की सीटें कम हुई हैं, लेकिन शरद पवार की एनसीपी से उसके ज्यादा ही विधायक जीते हैं। इसी तरह एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सीटें बढ़ी हैं, जबकि हिंदुत्ववादी की बजाय सेकुलर चोला धारण करने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिछड़ गई है। अब इन नतीजों के आधार पर अजित पवार की पार्टी असली एनसीपी होने का दावा करेगी तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी खुद को असली और बाला साहब ठाकरे की असल उत्तराधिकारी बताएगी। ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टियों के वजूद को बचाए रखने का संघर्ष होगा। आने वाले दिनों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे का विधायक दल टूटे तो हैरत नहीं होनी चाहिए।

शरद पवार का कहना है कि कटेंगे तो बंटेंगे का असर भी महाराष्ट्र के चुनावों में दिखा। बीजेपी की अगुआई वाले गठबंधन के खिलाफ राज्य का 11 फीसद मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हुआ। इसकी वजह से हिंदू वोट बैंक महायुति की ओर गोलबंद हुआ। वैसे जानकारों का मानना है कि मराठा आरक्षण की मांग रखने वाले मनोज जरांगे का पहले चुनाव लड़ने का ऐलान करना और बाद में शरद पवार आदि के दबाव में चुनाव से पैर पीछे खींचना भी महायुति की सफलता की वजह बना। इससे मनोज जरांगे की साख कमजोर हुई और मराठा वोटर महायुति की ओर लौट आया, जो लोकसभा चुनाव के दौरान उससे दूर हो गया था।

महाराष्ट्र के नतीजों से महायुति की अंदरूनी राजनीति पर भी असर पड़ने की संभावना है। भाजपा महाराष्ट्र को बिहार की राह पर ले चलना नहीं चाहेगी। उधर झारखंड के नतीजों ने एक रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के गठन के बाद कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है। हेमंत सोरेन यह रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे हैं। नतीजों ने साबित किया है कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को झारखंड की जनता ने स्वीकार नहीं किया। झारखंड की कमान बीजेपी की ओर से हिमंत विश्वशर्मा और शिवराज सिंह चौहान को दी गई थी। हिमंत इसमें अगर वे सफल होते तो उनकी राष्ट्रव्यापी छवि बनती। लेकिन वे इसमें नाकाम रहे हैं। अगर बीजेपी को झारखंड में कामयाबी मिलती तो शिवराज का भी कद बढ़ता। लेकिन फिलहाल इसमें ब्रेक लगता दिख रहा है। बीजेपी को चंपई सोरेन के जरिए कोल्हान में चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन चंपई कोई कमाल नहीं दिखा पाए। इसका असर उनके राजनीतिक कद पर भी पड़ेगा। बीजेपी को अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा और आदिवासी वोटरों के बीच भरोसा कायम करने के लिए सोचना पड़ेगा।

उपचुनावों में वायनाड से प्रियंका गांधी की जीत संभावित थी। लेकिन महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट उसके हाथ से निकल गई। उपचुनावों में सबसे हंगामा उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों को लेकर रहा। इनमें बीजेपी की बढ़त का मतलब साफ है कि योगी सरकार का मकबूल बना हुआ है। वैसे राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दलों को ही समर्थन मिला है। बिहार में प्रशांत किशोर का करिश्मा नजर नहीं आया, अलबत्ता एनडीए एक बार फिर मजबूती से उभरा है। इसका असर बिहार के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी दिखेगा।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

अशआर मिरे यूँ तो ज़माने के लिए हैं
कुछ शेर फ़क़त उन को सुनाने के लिए हैं
अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें
कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं
सोचो तो बड़ी चीज़ है तहज़ीब बदन की
वर्ना ये फ़क़त आग बुझाने के लिए हैं
आँखों में जो भर लोगे तो काँटों से चुभेंगे
ये ख़्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए हैं
देखूँ तिरे हाथों को तो लगता है तिरे हाथ
मंदिर में फ़क़त दीप जलाने के लिए हैं
ये इल्म का सौदा ये रिसाले ये किताबें
इक शख़्स की यादों को भुलाने के लिए हैं..!!

- जां निसार अख्तर

अब मैथिली और संस्कृत में भी पढ़ सकेंगे संविधान

● राष्ट्रपति ने किया विमोचन, पीएम मोदी-राहुल गांधी भी रहे मौजूद ● 2004 में अटल सरकार में मिला था आधिकारिक भाषा का दर्जा

नई दिल्ली/पटना (एजेंसी)। अगर आप संस्कृत या मैथिली भाषा में संविधान पढ़ना चाहते हैं तो अब आपकी ये इच्छी पूरी हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के मौके पर मैथिली और संस्कृत भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान की प्रतियां जारी कीं।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। यह मैथिली भाषा के लिए एक बड़ा कदम है, जिसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया था। संविधान दिवस के मौके पर आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैथिली और संस्कृत भाषा में संविधान की प्रतियों का विमोचन किया। यह कार्यक्रम संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बदलते दौर के भारत में एमपी ने विकास के सभी द्वार खोले : सीएम

कहा- प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति पथ पर हो रहा है अग्रसर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश भारत का दिल है, देश के सभी अंचलों के लोग यहां बसते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बदलते दौर में देश तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है, मध्यप्रदेश भी उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में दिन-दूनी-रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है। हेल्थ, टूरिज्म, आईटी, एजूकेशन, गारमेंट्स सहित हर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अधोसंरचना का क्षेत्र हो या अन्य मूलभूत सुविधाओं का क्षेत्र प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार औद्योगिक विकास और निवेश संवर्धन के लिए प्रभावी कार्य कर रही है। सड़क, बिजली तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए लैंड बैंक के मामले में मध्यप्रदेश ने देश के श्रेष्ठतम राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूके यात्रा के दौरान लंदन में एनआरआई समूह 'फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश' और प्रवासी समुदाय के साथ संवाद में यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का लंदन (यूके) में रॉयल नेशनल होटल में प्रवासी समुदाय और 'फ्रेंड्स ऑफ एमपी' के सदस्यों ने आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल सहित अनेक प्रतिष्ठित भारतीय प्रवासी शामिल रहे।

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है

कार्यक्रम को लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत और मध्यप्रदेश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत लंदन में सबसे बड़ा निवेशक है, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उनकी यात्रा सफल और उद्देश्यपूर्ण हो इसके लिए शुभकामनाएं दीं। 'फ्रेंड्स ऑफ एमपी' के संस्थापक सदस्य तथा एनआरआई श्री मनीष तिवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश में केवल वहीं के लोग नहीं बसते, बल्कि एमपी एक छोटा भारत है। उन्होंने कहा कि लंदन में मध्यप्रदेश के लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से ही फ्रेंडस ऑफ एमपी का गठन किया। श्री तिवारी ने भोपाल, जबलपुर, कान्हा-किसली सहित प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्यी से परिपूर्ण पर्यटन स्थलों की प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता को दुनिया ने स्वीकारा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन और उनकी नेतृत्व क्षमता ने विश्व में भारत की साख को स्थापित किया है। दुनिया के देशों में प्रधानमंत्री श्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की स्वीकार्यता ने भारत और भारतवासियों का गर्व और मान विश्व में बढ़ाया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को प्राप्त श्री मोदी के सशक्त और समर्थ नेतृत्व से भारतवासी स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के विकास क्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष-2003 तक मध्यप्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में कुल 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। सभी 55 जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज संचालित हैं। खनन, टूरिज्म के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। गारमेंट्स क्षेत्र में प्रति श्रमिक 5 हजार रुपये प्रति माह की दर से इंसेंटिव है, इसी प्रकार आईटी सहित अन्य क्षेत्रों में भी सुविधाएं प्रदान करने और प्रोत्साहन की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है, निवेशक और उद्योग समूह निवेश करें, मध्यप्रदेश भी आगे बढ़ेगा और हम सब मिलकर देश की प्रगति में सहभागी होंगे।

बैलेट पेपर से चुनाव के लिए अभियान चलाएगी कांग्रेस

देशव्यापी अभियान चलाने के लिए पार्टी ने कर दिया ऐलान

खरगे ने कहा-हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही हो 'चुनाव'

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और इसके लिए हम भारत जोड़ा यात्रा की तर्ज पर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। खरगे ने कहा, मैं एक बात कहूंगा कि पूरी शक्ति लगाकर ओबीसी, एससी, एसटी और कमजोर तबके के लोग जो वोट दे रहे हैं, वह फिजूल जा रहा है। हमारा कहना है कि सब छोड़ दो और बैलेट पेपर से वोट की हम मांग करते हैं। उन लोगों को मशीन अपने घर में रख लेने दो। अहमदाबाद में बहुत से गोदाम बने हैं, वे वहां ले जाकर मशीनों को रख दें। हमारी एक ही डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि वे कहां खड़े हैं। पार्टी अध्यक्ष ने कहा, 'मेरा कहना है कि हमारी पार्टी को एक मुहिम शुरू करनी चाहिए और सभी पार्टियों को भी इसके लिए साथ लेना चाहिए। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरे देश में अभियान चलाएंगे।' इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना से डरते हैं। लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि समाज का हर तबका अपनी हिस्सेदारी चाहता है और उसे मांग रहा है। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में आप देश में एकता चाहते हैं तो फिर नफरत फैलाना बंद करना होगा।

यही नहीं संविधान दिवस के मौके पर मल्लिकार्जुन खरगे ने यह मांग भी उठाई कि दो दिन संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी और उसकी रक्षा कैसे होगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी।

20 दिसंबर को होंगे राज्यसभा की छह सीटों के उपचुनाव

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 6 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 20 दिसंबर को होंगे और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। तीन सीटें आंध्र प्रदेश, एक ओडिशा, एक पश्चिम बंगाल और एक हरियाणा की है। ये सभी सीटें सदस्यों के इस्तीफे से खाली हुई हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर है और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर है।

चुनाव आयोग का ऐलान

ये राज्यसभा सीटें वेंकटरमण राव मोपिदेवी, बीडा मस्थान राव यादव, रयागा कृष्णैया (सभी आंध्र प्रदेश से), सुजीत कुमार (ओडिशा से), जवाहर सरकार (पश्चिम बंगाल से) और कृष्ण लाल पंवार (हरियाणा से) के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं।

राज्यसभा, संसद का उच्च सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की ओर से किया जाता है। ये उपचुनाव इन रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक हैं ताकि राज्यसभा में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व बना रहे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की है। देखना होगा कि इन सीटों पर कौन से नए चेहरे राज्यसभा पहुंचते हैं।

मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा गौतम अडाणी रिश्वत केस

मुंबई (एजेंसी)। अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने के आरोप का मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मद्रास हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गृह मंत्रालय को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। एडवोकेट और देसिया मक्कल शक्ति काची के प्रसिडेंट एमएल रवि ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से उन्होंने कहा कि अडाणी को तमिलनाडु सहित कई भारतीय राज्यों के व्यवसायियों, बिजली वितरण कंपनियों और भारतीय संस्थाओं के साथ सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को

सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। एडवोकेट ने तर्क दिया कि विदेशी देश ने भारत में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उसके बाद अभी भी भारतीय जांच एजेंसियां चुप हैं। वह केवल दर्शकों की तरह काम कर रही हैं, जो पूरे देश और 140 करोड़ नागरिकों का अपमान है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने सरकारी संस्थान में जनता के विश्वास को खत्म कर दिया है और देश के विकास में बाधा उत्पन्न की है। 24 नवंबर को इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई थी याचिका इससे पहले रविवार यानी 24 नवंबर को एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले की जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के आदेश और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की शिकायत ने अडाणी ग्रुप की गड़बड़ियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि आरोप इतने गंभीर हैं कि देश के हित में भारतीय एजेंसियों की ओर से भी इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 23 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 27 नवंबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संवैधानिक के कर्तव्यों को भी आत्मसात करें : जामवाल

संविधान की भावना को समझकर उसकी बातों को नीचे तक पहुंचाएं पार्टी कार्यकर्ता

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संविधान दिवस पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने संविधान में जो गलतियां की थीं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धीरे-धीरे उन्हें सुधार रहे हैं और संविधान को देश के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा संविधान को किताब माना परंतु भाजपा ने ग्रंथ मानकर सम्मान किया है। कांग्रेस ने 90 बार संविधान का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या की है। धारा-370 और 35 ए इस देश के अनुकूल नहीं थी,

मोदी जी ने संवैधानिक तरीके से उन्हें हटा दिया। महिला सशक्तीकरण की सिर्फ बातें होती थीं, लेकिन मोदी जी ने नारीशक्ति वंदन अधिनियम में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करके उसे साकार कर दिया। हमारा देश संविधान के मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि 2047 में जब हमारी आजादी को 100 साल पूरे होंगे, तब तक भारत एक विकसित देश बने। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया का नंबर-1 देश बने। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि देश में हर जगह हमारा नेतृत्व हो। आज संविधान दिवस पर पार्टी कार्यकर्ता इसके लिए काम करने का संकल्प लें और संवैधानिक अधिकार ही नहीं कर्तव्यों को भी आत्मसात करें। देश तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए एकजुटता जरूरी है। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता संविधान की मूल भावना को समझें और उसे समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रसारित करें। संगोष्ठी को भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक श्री रामेश्वर शर्मा एवं पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री रजनीश अग्रवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री एवं विधायक श्री भगवानदास सबनानी ने एवं आभार प्रदर्शन प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री आशीष उषा अग्रवाल ने किया। इस दौरान मंच पर पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री श्री माखन सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कांतदेव सिंह एवं श्रीमती सीमा सिंह जादौन उपस्थित रहीं।

व्यापम घोटाला, सात को सात साल की सजा

भोपाल। सीबीआई विशेष न्यायालय ने मंगलवार को व्यापम प्रकरण के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने आरक्षक भर्ती घोटाले के सात आरोपियों को सात-सात साल की सजा और दस-दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एस.टी एफ. भोपाल ने16 मई 2015 को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई ने अग्रिम विवेचना कर पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

सी.बी.आई. के लोक अभियोजक सुशील कुमार पाण्डेय ने बताया कि व्यापम द्वारा वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा साल 2013 में 07.04.13 को आयोजित की थी जिसमें 3 अभ्यथियों विवेक त्यागी, चरण सिंह सिकरवार तथा सुनील रावत ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठा कर पास करने के लिए दलालों मध्यस्तों से मिलीभगत कर परीक्षा पास की थी। आभ्यर्थी विवेक त्यागी के स्थान पर प्रतिरूपक संदीप नायक तथा बृजेन्द्र सिंह रावत ने, आभ्यर्थी चरण सिंह सिकरवार के स्थान पर प्रतिरूपक श्रीनिवास सिंघल ने, आभ्यर्थी सुनील रावत के स्थान पर प्रतिरूपक स्वर्गीय लेखराज रावत बंटी रावत तथा हरिओम रावत ने, परीक्षा दी थी। परिणाम स्वरूप उक्त 3 अभ्यार्थी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 प्रथम में पास हो गए थे।

न्यायालय ने 61 गवाहों, 300 दस्तावेजों और आर्टिकल्स आधार पर 3 अभ्यथियों विवेक त्यागी, चरण सिंह सिकरवार तथा सुनील रावत तथा 5 प्रतिरूप को संदीप नायक, बृजेन्द्र सिंह रावत, श्रीनिवास सिंघल तथा हरिओम रावत को सजा सुनाई है तथा सभी को न्यायालय ने सात-सात वर्ष कठोर कारावास तथा दस-दस हजार रुपए अर्ध दण्ड से भी दण्डित किया है।

संक्षिप्त समाचार

जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के चुनावों में बैलेट पेपर के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की बेंच ने टिप्पणी की, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है। जब आप हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज

की गई इस याचिका में बैलेट पेपर से वोटिंग के अलावा कई अन्य दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी। इसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर कोई कैंडीडेट इलेक्शन के दौरान वोटर्स को पैसे, शराब बांटने का दोषी पाया जाता है तो अयोग्य घोषित होगा।

दिल्ली में सीएम फेस का ऐलान नहीं करेगी बीजेपी !

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र के नतीजों के बाद दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं का जोश हाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कम ही वक्त बाकी है और पार्टी की ओर से अलग-अलग रणनीति तैयार की जा

रही है। एक ओर जहां दिल्ली में महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले को लागू करने की चर्चा है जिसमें लाडली बहना योजना जैसी स्कीम शामिल है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना ही मैदान में उतर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार में सफल रणनीति बनाएगा।

अपराधियों की कुर्क संपत्ति पीड़ितों में बांटेंगी यूपी सरकार

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों से कुर्की के जरिए अर्जित संपत्ति और आय को जब्त कर पीड़ितों में बांटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, और पुलिस कमिश्नरों को इस संबंध में एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी है। इस निर्देश के अनुसार, माफिया और अपराधियों द्वारा

अपराध से अर्जित संपत्ति पुलिस जब्त करेगी। जब्त की गई संपत्ति को अदालत के आदेश पर कुर्क किया जाएगा। कुर्की से मिलने वाली आय को पीड़ितों में वितरित किया जाएगा। आदेश के अनुसार, संबंधित जिले के डीएम 2 महीने के भीतर जब्त संपत्ति की नीलामी करेंगे और उससे प्राप्त आय को अपराध से प्रभावित लोगों में बांटेंगे। जानकारी के मुताबिक, अब गैंगस्टर ऐक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग ऐक्ट के बिना भी पुलिस काली कमाई जब्त या कुर्क कर सकेगी। अपराध से जुड़ी या जुटाई गई संपत्ति के अधिग्रहण या कुर्की का अधिकार मिल गया है।

रेलवे व विमान सेवा के विस्तार से खजुराहो आने वाले पर्यटकों को मिलेगी सुविधाएं

खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ होने से छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा : विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव व श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। श्री शर्मा ने खजुराहो से रीवा के मध्य विमान सेवा का वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।

विमान सेवा शुरू होने से और बेहतर होगी यातायात सुविधा, बढ़ेगा रोजगार- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने नई दिल्ली से खजुराहो से रीवा के मध्य नई विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कहा कि इस विमान सेवा के शुरू होने से खजुराहो आने वाले पर्यटकों को और बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। पर्यटन बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्र का विकास भी तेजी से बढ़ेगा। भोपाल से रीवा होते हुए खजुराहो के मध्य हवाई सेवा शुरू हुई है। रीवा-खजुराहो-रीवा विमान सेवा की सौगात देने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का खजुराहो लाकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक आभार जताता हूं। इस दौरान खजुराहो में विधायक श्री अरविन्द पटेरिया उपस्थित रहे।

क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रियों से की मुलाकात

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से भेंटकर खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के कटनी जंक्शन व खजुराहो रेलवे स्टेशन पर विभिन्न विकास कार्यों और रेलमार्ग से आने वाले पर्यटकों व यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेल सुविधाओं के विस्तार हेतु आग्रह किया। श्री शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक विजय पर बधाई भी दी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंटकर खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय शीघ्र शुरू करने का आग्रह कर शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। श्री शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ होने से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा भी मिल सकेगी। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

जो दलितों की बात करेगा, उसका माइक बंद होगा

कांग्रेस के कार्यक्रम में माइक बंद होने पर बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी, वहां जाति जनगणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने ये बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहे संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। राहुल ने कहा कि अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15 फीसदी दलित हैं, 15 फीसदी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं ये नहीं पता। 90 फीसदी हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आई है। राहुल ने कहा कि जो भी इस देश में 3 हजार साल से दलितों की, आदिवासियों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है।

सरकार सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहती है

राहुल बोले कि आपके सामने दीवार खड़ी है। आपके सामने दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया।

सावधान ! फिर से बिगड़ने वाला है मौसम

- बढ़ती ठंड के बीच बारिश के बन रहे आसार, अलर्ट जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। मौसम तेजी से करवट ले रहा है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मंगलवार सुबह दिल्ली में धुंध की एक परत छाई रही। सीपीसीबी के अनुसार कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सोमवार को कुछ सुधार देखा गया था और यह 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। इसके अनुसार, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 281 दर्ज किया गया, जबकि रविवार को शाम चार बजे यह 318 था। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.7 डिग्री अधिक है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के पांच

जिलों लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में 30 नवंबर को हल्की बारिश-हिमपात का पूर्वानुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के बाकी हिस्सों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा। उधर, बीते दिनों हुई बर्फबारी से जनजातीय क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। राज्य के चार स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद के तीन दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में लगभग दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। शिमला में न्यूनतम तापमान 9.0, सुंदरनगर 5.5, भुंतर 3.5, कल्पा 0.6 और केलांग -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

आंध्र प्रदेश में 29 नवंबर तक भारी बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 26 से 29 नवंबर तक चार दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इससे ठंड का प्रकोप और बढ़ जाएगा आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के समुद्र में एक अवदाब (डिप्रेशन) के प्रभाव के कारण भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने मंगलवार से शुक्रवार तक दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा 29 नवंबर को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यनम क्षेत्र में भी बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने विज्ञप्ति में कहा, 'रविवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग और समीपवर्ती पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के मध्य क्षेत्रों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया और तीव्र होकर अवदाब में बदल गया है।' आईएमडी ने भारी बारिश के अलावा 27 से 29 नवंबर तक राज्यभर में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान जताया है और यह एससीएपी और रायलसीमा तक सीमित रहेगी।

बड़बोले संजय राउत को पूर्व सीजेआई का करारा जवाब

गिनवा कर दी बड़े फैसलों की फेहरिश्त, खामियां भी बताई

मुंबई (एजेंसी)। चंद्रचूड़ साहब को इतिहास माफ नहीं करेगा, महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद संजय राउत ने पूर्व चीफ जस्टिस की विधायकों की अयोग्यता का मामला लटकाने का आरोप लगाया था। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यूबीटी नेता संजय राउत को ऐसे बड़े मुद्दे गिनवा दिए, जिस पर फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था। एक इंटरव्यू में पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने नौ बेंच की खंडपीठ और सात बेंच वाली पीठ ने महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि क्या किसी पार्टी या व्यक्ति तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। माफ कीजिएगा, यह अधिकार चीफ जस्टिस के पास है। सांसद संजय राउत ने हार का ठीकरा पूर्व मुख्य जस्टिस के सिर फोड़ने की कोशिश की।

कोर्ट के पास सीमित मैनपावर, बैलेंस बनाना जरूरी होगा

बता दें कि 2022 में एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। शिंदे गुट ने भी इस केस में जवाबी याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फैसला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया, जिन्होंने शिंदे गुट को 'असली' शिवसेना घोषित किया। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिस पर फैसला नहीं हो सका और शिंदे सरकार का कार्यकाल भी खत्म हो गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 20 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले लंबित पड़े हैं।

अयोध्या के मिल्कीपुर में जनवरी में हो सकता है उपचुनाव

लखनऊ (एजेंसी)। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सोमवार को भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने याचिका वापस लेने को मंजूरी दी। गोरखनाथ ने कहा कि सपा चुनाव लटकाना चाहती थी। इसलिए कोर्ट में वकील खड़े किए थे। ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए, सपा के झूठ का पर्दाफाश भी हो जाएगा। गोरखनाथ और निर्दलीय उम्मीदवार शिवमूर्ति ने 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई थी। कहा था कि वे अब यह केस नहीं लड़ना चाहते। यह मामला 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद ने चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल किया।

आरएनटीयू के विधि विभाग व एनएसएस के द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हुआ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई गई

गीता और संविधान दोनों हमें हमारे कर्तव्यों का निर्वहन सिखाते हैं : प्रो. अमिताभ सक्सेना

भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के विधि विभाग व राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसका समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं व राष्ट्रीय संगोष्ठी से हुआ। भारतीय पवित्र ग्रंथ गीता का दर्शन और भारतीय संविधान पर इसका प्रतिबिंब विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो अमिताभ सक्सेना ने संबोधित करते हुए श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। श्री सक्सेना ने कहा कि भगवद्गीता भारत के पवित्र ग्रंथों का प्रतिनिधि ग्रंथ है जो हमें सही तरीके से जीवन जीना सिखाता है। गीता बताती है कि धर्म का अभिप्राय किसी संप्रदाय विशेष के भौतिक अभ्यासों से नहीं है अपितु धर्म का अभिप्राय है अपने कर्तव्य-कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हुए चलना। 'कर्म ही पूजा' गीता का सार भी है। इसी प्रकार भारतीय संविधान भी हमारे कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति हमें प्रेरित करता है। संविधान में वर्णित हमारे मौलिक कर्तव्य हमें न केवल देश व देश में स्थापित संस्थाओं का सम्मान सिखाते हैं बल्कि देश की नदियों, वनों व वन्यजीवों के प्रति भी सह अस्तित्व की भावना सिखाता है। यह न केवल गीता बल्कि हमारे उपनिषदों का भी सार है जिसका प्रतिबिंब हमें भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। वहीं विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति डॉ संगीता जौहरी ने कहा कि आज कि युवा पीढ़ी को गीता व संविधान दोनों का अध्ययन करना चाहिए। ताकि कोई भी आपको दिग्भ्रमित न कर सके।

भस्म आरती में शामिल हुए क्रिकेटर अक्षर पटेल-रवि विश्नोई

इंदौर में मुश्ताक अली ट्राफी खेलने आए हैं कई दिग्गज खिलाड़ी

भोपाल। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अक्षर पटेल, रवि विश्नोई और अभिषेक देसाई मंगलवार को महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। वे तड़के चार बजे मंदिर पहुंचे। भस्म आरती के दौरान करीब दो घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर भगवान को दूध अर्पित किया। बता दें कि मुश्ताक अली ट्राफी में शामिल होने के लिए कई दिग्गज खिलाड़ी इंदौर पहुंचे है। अक्षर पटेल,रवि विश्नोई

और अभिषेक देसाई के साथ अन्य खिलाड़ी भी आरती में शामिल हुए। अक्षर पटेल और रवि विश्नोई ने भगवान मंदिर की देहरी से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। भस्म आरती सम्पन्न होने के बाद सभी ने नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना मांगी। अक्षर पटेल ने कहा कि मैंने अपने लिए नहीं मांगा है। मुझे हर साल बाबा महाकाल बुलाते हैं, बस वे बुलाते रहे। मेरे लिए जो अच्छा होगा बाबा महाकाल मुझे दे देते हैं। दूसरी बार भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने महाकाल मंदिर पहुंचे रवि विश्नोई ने कहा कि महादेव की कृपा मुझ पर बनी रहे। बहुत अच्छा लगता है महाकाल मंदिर आना, मैं दूसरी बार आया हूं। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कुनाल पंड्या महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। जहां उन्होंने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया था।

डीएपी लेने लाइन में लगे किसानों पर पुलिस बरसा रही लाठियां

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले- किसानों को खाद नहीं दे पा रही सरकार

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खाद संकट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें खेती-किसानी पर गहरा आघात कर रही हैं। एक तरफ किसानों को पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता, दूसरी ओर उन्हें समय पर खाद भी नहीं मिल रही। खेती की लागत इतनी

बढ़ा दी गई है कि किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। मध्यप्रदेश के किसान कई-कई दिनों तक खाद लेने के लिए कतारों में खड़े हैं। भाजपा की सरकार में किसान पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेने की अपेक्षा सात समुंदर पार सत्ता का लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि मध्यप्रदेश में रबी सीजन में गेहूं, चना, मटर, सरसों, गन्ना, अलसी जैसी प्रमुख फसलें पैदा की जाती हैं। डीएपी खाद का संकटः पटवारी ने कहा मध्यप्रदेश और देश में डीएपी खाद का गहरा संकट है। प्रदेश में रबी सीजन में भारत सरकार द्वारा 8 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराने की सहमति दी गई थी। लेकिन, 20 नवंबर 2024 तक मात्र 4.57 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराई गई और अब तक प्रदेश में मात्र 2.91 लाख मैट्रिक टन डीएपी का विक्रय किया गया। डीएपी और कॉम्प्लेक्स खाद सिर्फ बोवनी के समय ही उपयोग किया जाता है। अभी अक्टूबर-नवम्बर माह बोवनी का समय होता है, मगर भारत सरकार द्वारा डीएपी उपलब्ध कराने के आश्वासन का आधा खाद भी नहीं दिया है। जहां प्रदेश में यूरिया की जरूरत 20 लाख मैट्रिक टन की है। वहां उपलब्धता 12.70 लाख मैट्रिक टन मात्र की है और 20 नवंबर 2024 तक इसमें से भी केवल 7.69 लाख मैट्रिक टन वितरित किया गया। पटवारी ने सोयाबीन की फसल लगाने वाले किसानों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में लगभग 52 लाख हेक्टेयर भूमि में सोयाबीन की बुवाई हुई है। 55 से 60 लाख टन सोयाबीन उत्पादित हुआ है। सोयाबीन किसानों को फसलों के दाम लागत मूल्य जितने भी नहीं मिल पा रहे थे। कृषि मंत्री और प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राइस सपोर्ट स्कीम पर सोयाबीन को समर्थन मूल्य 4892 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने का भरोसा दिया था। जबकि हकीकत कुछ और ही है। राज्य सरकार ने 2024-25 खरीफ सीजन के लिए 10 सितम्बर 2024 को 27.34 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन खरीदने का अनुरोध किया था। मगर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए मात्र 13,68,045 मैट्रिक टन सोयाबीन खरीदने की अनुमति ही केंद्र द्वारा दी गई। उसमें से भी 25 अक्टूबर से 21 नवंबर 2024 तक मात्र 56768.85 मैट्रिक टन सोयाबीन खरीदा गया।

एमपी में रात का तापमान 6 डिग्री से नीचे गिरा

भोपाल-जबलपुर समेत 10 शहरों में 10 डिग्री से कम, दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

भोपाल। मध्यप्रदेश में रात का टेम्प्रेचर 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। उज्जैन में सोमवार रात का पारा एक डिग्री गिरकर 11.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक दिन ये 12.2 डिग्री था। इंदौर में पिछले 24 घंटों से ठंड ने असर दिखाना शुरू किया। सोमवार को दिन का तापमान 27.5 (-2) डिग्री और रात का तापमान 1 डिग्री लुढ़ककर 12.4 (-1) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह विजिबिलिटी 1200 मीटर थी और मौसम साफ है। सबसे कम तापमान हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 5.6 डिग्री रहा। भोपाल, जबलपुर समेत 10 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम है। मौसम विभाग, भोपाल की वैज्ञानिक शिल्पा आप्टे ने बताया, अगले 3 से 4 दिन तक कड़ाके की ठंड के आसार नहीं हैं। दिसंबर में मौसम बदलेगा और तेज सर्दी पड़ेगी।

म.प्र.सरकार ने 5 हजार करोड़ का और लिया कर्ज

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बाजार से फिर पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। यह कर्ज रिजर्व बैंक की मुंबई शाखा के माध्यम से दो हिस्सों में लिया गया है। दोनों ही कर्ज पर साल में दो बार ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा।

पहला कर्ज ढाई हजार करोड़ रुपयों का है, जिसे 20 साल बाद चुकाया जाएगा, जबकि दूसरा ढाई हजार करोड़ रुपये का कर्ज 14 साल में चुकाया जाएगा।

वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार अब तक 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब नया कर्ज मिलाकर यह राशि बढ़कर 25 हजार करोड़ रुपये हो गई है।

प्रदेश पर अब 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो गया । स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश का कुल बजट 3.65 लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन इससे अधिक मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज है।

युवतियों से छेड़छाड़ करने वाला साइको भोपाल में अरेस्ट

लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, ऐक्टिवा में मिले लड़कियों के अंडरगारमेंट्स

भोपाल। युवतियों से छेड़खानी करने वाले साइको युवक को पुलिस ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया है। पिछले एक महीने से वह चूना भट्ठी के यशोदा विहार कॉलोनी में युवतियों को परेशान कर रहा था। आरोपी के पास से पुलिस को लड़कियों के अंडरगारमेंट्स मिले हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपी मास्क और चश्मा पहने रहता था। अपनी एक्टिवा की नंबर प्लेट पर कागज चढ़ा रखा था। आरोपी की पहचान गौतम नगर निवासी इजहार खान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उसके मां-पिता टीचर हैं। रात में थाने आए पिता ने बताया कि उन्हें बेटे की इस हरकत की जरा भी भनक नहीं थी। वह कहां जाता है, किससे मिलता है, इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। बेटे की यह हरकत सुन पिता भी शर्मसार हो गए। पुलिस के मुताबिक, चूना भट्टी पुलिस ने उसकी जेब और स्कूटर की डिग्गी से बड़ी मात्रा में लड़कियों के अंडरगारमेंट्स बरामद किए हैं। यह गारमेंट्स वह कहां से लाता था और इनका क्या करता था, पुलिस इस बारे में

पता कर रही है। आरोपी ने छेड़छाड़ की दो वारदातें कबूल कर ली हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि चूना भट्टी इलाके में सोमवार को 2 जगह से छेड़छाड़ की शिकायत आई। दोनों ही शिकायतें दोपहर बाद की हैं। एक युवती ने डायल-100 को कॉल किया था। पुलिस आरोपी की तलाश में थी। इस बीच शाम को उसने एक और वारदात को अंजाम दे दिया। इस युवती ने शोर मचाया, इसके बाद लोगों ने आरोपी को घेरकर पुलिस को सूचना दी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद थाने पहुंचीं दोनों पीड़ित युवतियों ने एफआईआर दर्ज कराई। अब पुलिस उन युवतियों का पता लगा रही है, जो आरोपी की छेड़छाड़ का शिकार हो चुकी हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी युवतियों को डराता-धमकाता भी था। पिछले एक महीने से छेड़खानी की शिकायतें आ रही थीं। पुलिस के पास इनपुट था कि एक्टिवा से चलने वाला नकाबपोश लड़का, लड़कियों को छेड़कर भाग जाता है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

अब 30 में ले पाएंगे खसरा-खतौनी की प्रमाणित प्रति

प्रदेश की मोहन यादव सरकार का किसानों के हित में बड़ा कदम

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें अपनी जमीन के रिकॉर्ड आसानी से और कम कीमत पर मिलेंगे। मोहन सरकार ने ई-खसरा परियोजना शुरू की है, जिसके तहत किसान सिर्फ 30 रुपये में खसरा-खतौनी की प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ई-खसरा परियोजना की शुरुआत हुई है। इस परियोजना का लक्ष्य जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और किसानों तक आसानी से पहुंचाना है। इससे जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर लगाम

लगेगी। अब किसानों को केवल 30 रुपये प्रति पन्ने पर खसरा, खतौनी और नक्शे की प्रमाणित प्रति मिलेगी। खसरा और खतौनी किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनमें जमीन और खेती से जुड़ी सारी जानकारी होती है। पहले किसानों को केवल खसरा-खतौनी की फोटोकॉपी मिलती थी, जिसमें कई बार हेराफेरी की आशंका रहती थी। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। कई बार तो किसानों के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती थी। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें खसरा-खतौनी में बदलाव करके किसानों को ठगा गया है। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के आने से ऐसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। किसानों को अब प्रमाणित दस्तावेज मिलेंगे, जिससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। ई-खसरा परियोजना के तहत, प्रदेश की सभी तहसीलों में आईटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन सेंटर्स में एक निजी कंपनी काम कर रही है, जिसे सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। किसान इन सेंटर्स में जाकर आसानी से अपने जमीन के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। खसरा (बी-1) और नक्शे की कॉपी के लिए 30 रुपये प्रति पन्ना देना होगा।

पीएम मोदी के प्रोजेक्ट में लापरवाही, कलेक्टर का एक्शन

9 कर्मचारियों को सस्पेंड, 91 को कारण बताओ नोटिस जारी

भोपाल। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड बनाने में न्यूनतम उपलब्धि, लापरवाही व निरीक्षण कार्य में अनुपस्थित रहने जैसे कारणों के चलते 04 बीएमओ, 08 बीसीएम, 08 वीपीएम, 69 सीएचओ, 01 नेत्र सहायक सहित एक सैकड़ा कर्मचारियों कार्यवाही की गई है। इनमें से 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, वहीं शेष को नोटिस जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय ऋषीश्वर ने बताया कि कलेक्टर शिवपुरी रविन्द्र कुमार चौधरी की पहली प्राथमिकता पर आदिवासी, गरीब व पिछड़े वर्ग के आयुष्मान कार्ड तैयार कराकर उन्हें लाभ प्रदान कराना है। इसके लिए वह निरंतर बैठक, निरीक्षण करने के साथ चेतावनी भी दे रहे हैं। इसके बावजूद पीव्हीटीजी वर्ग, सीनीयर सीटिजन एवं बीओसीडब्लू वर्ग के आयुष्मान कार्ड बनाने, उनकी मॉनिटरिंग कार्य करने में लापरहवाही को देखते हुए खंड चिकित्सा अधिकारियों, सीएमएचओ की अनुशंसा पर स्वंय कलेक्टर शिवपुरी व उनके निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है। इस कार्रवाई में आयुष्मान कार्ड बनाने में न्यूनतम उपलब्धि वाले 04 बीएमओ, 08 बीसीएम, 08 बीपीएम, 69 सीएचओ और नेत्र सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं विकासखंड पिछोर 04 सुपरवाईजर, खनियांधाना विकासखंड से 03 एमपीडब्यू, बदरवास विकासखंड से 01 एमपीडब्लू व पोहरी विकासखंड से 1 एलएचव्ही को निलंबित किया गया है। पीव्हीटीजी, सीनीयर सीटिजन एवं बीओसीडब्लू वर्ग के आयुष्मान कार्ड बनाने में न्यूनतम उपलब्धि वाले विकासखंड पिछोर के प्रभारी बीपीएम अखिलेश कनेहरिया, प्रभारी बीसीएम विवेक पचौरी एवं 16 सीएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विकासखंड करैरा के प्रमुखखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रदीप शर्मा, बीसीएम अवधेश गौरैया एवं प्रभारी बीपीएम विजय सोनी एवं 06 सीएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। विकासखंड खनियांधाना के प्रभारी बीएमओ डॉ.अरूण झस्या, प्रभारी बीसीएम हरीश चौरसिया, प्रभारी बीपीएम मोहन गुप्ता एवं 5 सीएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विकासखंड बदरवास प्रभारी बीएमओ डॉ चेतेन्द्रि कुशवाह, बीसीएम दुर्गादास धनोलिया, बीपीएम सुमन बडोले एवं 6 सीएचओ, विकासखंड नरवर से बीएमओ डॉ एलडी शर्मा, बीसीएम सोनू जैन, प्रभारी बीपीएम अजयकांत गहलोत एवं 11 सीएचओ विकासखंड पोहरी से वीपीएम सतेन्द्र पटेरिया, बीसीएम शेर सिंह रावत एवं 12 सीएचओ, विकासखंड सतनवाडा से बीसीएम संतोष शर्मा, वीपीएम पूर्णिमा शर्मा एवं 6 सीएचओ, विकासखंड कोलारस से बीसीएम विवेक पचौरी , वीपीएम रजनीश श्रीवास्तव एवं 7 सीएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। इसके साथ ही एक नेत्र सहायक जितेन्द्र रघुवंशी विकासखंड बदरवास को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। आयुष्मान कार्ड बनवाने एवं मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने वाले 04 सुपरवाईजर वीके शर्मा पिछोर, वीरेन्द्र गुप्ता पिछोर, खेमराज आदिवासी पिछोर, सुखदेव पांडे पिछोर को निलंबन किया गया। इसी प्रकार 04 एमपीडब्लू को निलंबित किया गया है, जिनमें विकासखंड बदरवास से मुकेश शर्मा एमपीडब्यू, प्रकाशचंद राजपूत एमपीडब्लू, खनियांधाना, ओमप्रकाश जाटव खनियांधाना, संजय गुप्ता एमपीडब्लू खनियांधाना को निलंबन किया गया। इसके साथ ही पोहरी विकासखंड से एलएचव्ही स्वरूपी मांझी को निलंबित करने की कार्यवाही की गई।

जंगली जानवरों के हमले में मौत पर अब मिलेंगे 25 लाख

मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाई मुआवजा राशि, दो किश्तों में मिलेगी

भोपाल। वन्यजीव हमलों में होने वाली मौतों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। पहले यह राशि सिर्फ 8 लाख रुपये थी। नई व्यवस्था में पीड़ित परिवार को तुरंत 10 लाख रुपये मिलेंगे और बाकी 15 लाख रुपये की एफडी बनाई जाएगी। यह कदम मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है। मध्य प्रदेश का मुआवजा अब महाराष्ट्र के बराबर हो गया है। यह महत्वपूर्ण बदलाव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद आया है। वन विभाग इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इससे पहले, वन्यजीव हमले में मौत पर मिलने वाला मुआवजा महाराष्ट्र के मुकाबले काफी कम था। अब बढ़ी हुई राशि से पीड़ित परिवारों को कुछ आर्थिक राहत मिल सकेगी। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 10 लाख रुपये की तत्काल दी जाएगी। बाकी 15 लाख रुपये की एफडी की जाएगी। इस एफडी में से 10 लाख रुपये 5 साल बाद और 5 लाख रुपये 10 साल बाद मिलेंगे। यह राशि मृतक के वारिसों को ब्याज समेत

मिलेगी। वर्तमान में, वन विभाग के पास हर साल वन्यजीव हमलों में मौत के लगभग 40 मामले आते हैं। इसके लिए करीब 3 करोड़ रुपये का बजट रखा जाता है। नया प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होने के बाद इस बजट में भी इजाफा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की व्यवस्था है, जहां वन्यजीव हमले में मौत पर 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में अभी तक मौत पर 8 लाख, इलाज पर खर्च की गई राशि और स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये दिए जाते थे। वहीं, छत्तीसगढ़ में 6 लाख, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 5-5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में बाघ, तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना बढ़ रहा है। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पिछले पांच सालों में वन्यजीव हमलों में 292 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2023-24 में अक्टूबर तक वन्यजीव हमलों में मौत, घायल होने और पशुओं के नुकसान के मामलों में 15 करोड़ 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। यह आंकड़ा इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। मध्य प्रदेश से सटे राज्यों में मुआवजा राशि अलग-अलग है। छत्तीसगढ़ में जनहानि पर 6 लाख रुपये मिलते हैं, लेकिन स्थायी अपंगता पर कोई मुआवजा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनहानि पर 5 लाख और स्थायी अपंगता पर 4 लाख रुपये मिलते हैं। राजस्थान में जनहानि पर 5 लाख और स्थायी अपंगता पर 3 लाख रुपये मिलते हैं। गुजरात में जनहानि पर 5 लाख और स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये मिलते हैं। महाराष्ट्र में जनहानि पर 25 लाख और स्थायी अपंगता पर 7.5 लाख रुपये मिलते हैं।

संपादकीय

संभल में हिंसा : दोषी कौन?

उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की हिंसा और उसमें 5 लोगों की मौत के बाद अब यह साफ होता जा रहा है कि वहां हिंसा जानबूझकर भड़काई गई। वरना मस्जिद के सर्वे को लेकर अनावश्यक तनाव फैलाने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि सर्वे और भी मस्जिदों में हुए हैं और सर्वे भर हो जाने का मतलब यह नहीं है कि मस्जिद पर किसी और का अधिकार हो गया। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उससे यह पता चलता है कि सर्वे की आड़ में मस्जिद में तोड़ फोड़ की अफवाह इंटरनेट के माध्यम से फैलाई गई। परिणामस्वरूप हजारों लोग, जिनमें मुंह पर कपड़ा बांधे कई बच्चे और युवा सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पथराव किया, फायरिंग और आगजनी तक हुई। पुलिस और प्रशासन ने जैसे तैसे स्थिति को संभाला। लेकिन निहित स्वार्थों और कट्टरपंथियों के हाथों में खेलने का नतीजा यह हुआ कि पांच युवाओं को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतकों के परिजनों का कहना है कि पांच में चार पुलिस की गोली से मरे तो पुलिस का कहना है कि गोली पुलिस ने नहीं, बल्कि भीड़ में से किसी ने चलाई, जिसके कारण इन युवाओं की मौत हुई। संभल में हिंसा निश्चित रूप से किस कारण से शुरू हुई, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यूपी में नौ सीटों पर हुए उपचुनाव में से 7 पर भाजपा की जीत के बाद उपजे आक्रोश के परिणामस्वरूप यह हिंसा भड़काई गई। स्थानीय सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने बयान दिया कि संभल में मस्जिद कयामत तक रहेगी। पुलिस ने सांसद बर्क और सदर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल सहित हिंसा फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 800 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि विगत 19 नवंबर, को संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ। वहां हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका लगाई। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद पहले श्रीहरिहर मंदिर हुआ करती थी। इसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। हिंदू पक्ष ने यह याचिका संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई थी। तीन प्रमुख किताब/रिपोर्ट को आधार बनाकर मस्जिद से पहले यहां मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष की याचिका पर अदालत ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए। कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही एडवोकेट कमिश्नर रमेश चंद राघव सर्वे कराने पहुंचे। सर्वे टीम शाम 5.30 बजे मस्जिद पहुंचे। सर्वे करीब दो घंटे चला। इसके बाद टीम चली गई। लेकिन 24 नवंबर को टीम सुबह 6 बजे दोबारा सर्वे करने मस्जिद पहुंची। प्रशासन का कहना है कि शाम को सर्वे ठीक से न हो पाने के कारण दूसरे दिन यह काम किया गया। आसपास पुलिस और दूसरी बार सर्वे की बात पता चलते ही लोगों को शक हुआ। धीरे-धीरे शाही जामा मस्जिद के बाहर लोग जुटने लगे। सुबह करीब 7 बजे याचिकाकर्ता और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कुछ लोगों के साथ मस्जिद के बाहर पहुंचे। ये लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे। बताया जाता है कि सर्वे के दौरान मस्जिद में वजूखाने की गहराई नापने के लिए उसका पानी खाली कराया गया। लोग समझे कि मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है। इसके बाद वहां भीड़ जुटने लगी और पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि मस्जिद में तोड़फोड़ की अफवाह किसने फैलाई। इसी संदर्भ में सपा नेता अखिलेश यादव का सवाल है कि जब एक बार मस्जिद का सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार इसकी क्या जरूरत थी। प्रशासन ने एक बार में ही सर्वे की कार्रवाई पूरी क्यों नहीं की? अगर दूसरी बार सर्वे किया गया तो स्थानीय लोगों और मस्जिद प्रबंधन को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। दरअसल सरकार को देश में ऐसे कितनी मस्जिदें हैं, जिनके पहले मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, इसकी सूची तैयार कर उसका पुरातात्विक अध्ययन कराना चाहिए। यह काम सभी पक्षों को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए। अन्यथा ऐसे विवाद हिंसक रूप लेते रहेंगे।

नजरिया

शाहिद नकवी
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

महाराष्ट्र में क्यों कारगर नहीं हुआ संविधान बचाने का नारा

सत्य है कि हर हार के बाद भाजपा के नेता सबक लेते हैं। लेकिन हर जीत के बाद विपक्ष के गुब्बारे फूल जाते हैं। जैसा लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिला कि भाजपा जीत के बाद भी खामोश नहीं रही। जबकि विपक्ष सत्ता से दूर रहने के बाद भी रणनीतिक भूल करता रहा। यहां तक कि वह ठीक से गठबंधन धर्म भी नहीं निभा सका। उत्तर प्रदेश में सपा अपनी सफलता पर इतना इतराने लगी कि उसने उप चुनाव में कांग्रेस से बिना बात किए हुए ही नौ में से सात सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। ऐसे में कांग्रेस ने मैदान से हटना ही बेहतर समझा। राहुल गांधी एक बार भी यूपी नहीं आये। वह केरल और महाराष्ट्र में ही डटे रहे।लोकसभा की तर्ज पर इंडिया गठबंधन जाति जनगणना का कार्ड खेलता रहा। जबकि एनडीए ने योगी के नारे बंटेंगे तो कटेंगे के साथ एक हैं तो सेफ हैं जोड़ कर जातीय एकजुटता से इसकी काट निकाल ली।

नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक वोटों की गोलबंदी में ये नारा रामबाण साबित हुआ। इसी नारे की बिना पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा के उपचुनाव में 7 पर भगवा फहरा गए। हां झारखंड में कांग्रेस भले ही गुब्बारे फुलाती रहे,लेकिन महाराष्ट्र और यूपी उप चुनाव के नतीजे कई साफ संदेश दे गए हैं। अब तक ये रवायत रही है कि उप चुनाव सत्ता पक्ष के समर्थन वाला प्रस्ताव ले कर खामोशी से गुजर जाते हैं,लेकिन ये उपचुनाव शोरगुल मचाते हुए अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के पीडीए और माई समिकरण पर भी सवालिया निशान लगा कर गुजरें हैं। कुंदरकी और करहल विधानसभा सीटों के नतीजे काबिले गौर हैं। सपा मुखिया की पुश्तैनी सीट करहल में 22 के चुनाव में सपा 64 हजार मतों से जीती थी, लेकिन इस बार जीत का अंतर केवल 14 हजार रहा। वहीं कुंदरकी जहां भाजपा तीन दशक से जीत के लिए तरस रही थीं, वहां सपा के मुस्लिम उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। जबकि यहां 65 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट पर सपा सहित 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन वोटों का बंटवारा ऐसा नहीं हुआ जिससे सपा की हार होती।

भाजपा के रामवीर सिंह को 170371 वोट मिले और वह 144791 वोट के भारी अंतर से जीत गए। सपा के रिजवान को केवल 25580 वोट मिले।वोटों का अंतर बताता है कि यहां मुस्लिम वोट भाजपा के खाते में भी गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक रामवीर सिंह ने अरबी गमछा और मुस्लिम टोपी पहन कर मुस्लिमों के बीच जा कर बहुत समय बिताया। संघ और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी यहां ढंग से सक्रिय रहा। फौरी तौर पर कोई नहीं मानता कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया।लेकिन मतदान प्रतिशत और भाजपा उम्मीदवार को मिले मत ये साबित करते हैं कि बिना मुस्लिम समर्थन के रामवीर सिंह की इतनी बड़ी जीत सम्भव नहीं। इसी तरह करहल में सपा की जीत का अंतर कम होना ये बताता है कि उसके वोट बैंक में सेंधमारी उसके परम्परागत गढ़ तक पहुंच गई है।

फूलपुर में भी सपा का पीडीए हवा में ही रहा,लोकसभा में यहां 18000 की बढ़त 11 हजार की हार में बदल गई। सपा पीडीए का नारा देती है और सुरक्षित सीट पर परिवार को प्रमुखता देती है,जाहिर है ये बात कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं को भी खटकी होगी। ये भी काबिले गौर है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपानीत महा आघाड़ी की प्रचंड जीत और विपक्षी कांग्रेसनीत महाविकास आघाड़ी की दारूण पराजय एवं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में यूपीए की सत्ता में शानदार वापसी के मूल में कॉमन बात इन राज्यों में सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ देना है।

मप्र से निकला फॉर्मूला अब रंग दिखा रहा यह बात शीशे की तरह साफ है कि महिलाओं को आर्थिक मदद देकर मतदाता के रूप में उनका समर्थन जीतने का जो गेमचेंजर प्लान मप्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ईजाद किया था,वह न सिर्फ भाजपा बल्कि हर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए जीत का शर्तिया नुस्खा साबित हो रहा है। यही कारण है कि महिलाएं बड़ी संख्या में वोट कर रही हैं और उस सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में वोट कर रही हैं, जो हर माह उनके खाते में निश्चित राशि सीधे जमा कर रही है। सभी मुख्यमंत्री इस आर्थिक मदद को राज्य की बहनों को ‘भाई का नेग’ करार दे रहे हैं। बदले में बहनाएं उन पर वोट न्यौछावर कर रही हैं। महाराष्ट्र में यह कमाल युति सरकार की ‘लाडकी बहिण’ योजना ने तो झारखंड में झामुमो गठबंधन सरकार की ‘मइया सम्मान योजना’ ने किया।इसके पहले मध्यप्रदेश,राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकारों की वापसी राह महिला आधारित योजनाओं ने बनाई थी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ‘लाडकी बहिण योजना’ शुरू की थी। इस योजना के तहत, 21 से 65 साल की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की मदद दी जाएगी, जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख से कम होगी इस योजना के तहत राज्य की एक करोड़ महिलाओं को फायदा मिलता है। महाराष्ट्र में 65.22 फीसदी महिला वोटरों ने वोटिंग की थी।इसी तरह झारखंड में भी सोरेन सरकार ‘मंईयां योजना’ चलाती है। इसके तहत 21 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये की मदद मिलती है। हालांकि, ये मदद उन्हीं महिलाओं को मिलती है, जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपये से कम है।इस योजना से 48 लाख महिलाओं को फायदा होता है।

चुनाव से पहले सोरेन सरकार ने मंईयां योजना की राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर 2,500 करने का ऐलान किया। आंकड़ों के मुताबिक, कुल महिला वोटरों में से 70.46 फीसदी ने वोट डाला। महिलाओं की ये जबरदस्त वोटिंग सोरेन सरकार के लिए निर्णायक साबित हुई। यानी मंहगाई और बेरोज़गारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर मुफ्त की रेवड़ी भारी है।खाद्य मंहगाई चरम पर है,लेकिन इसे किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। जबकि बेरोज़गारी के आंकडों पर पहले ही ताला लगा है। नई सदी में महिलाएं पार्टियों का राजनीतिक भविष्य तय कर रही हैं। ये बात अलग है कि अभी कोई राजनीतिक दल राजनीति में महिलाओं को उनका वाजिब हक देने के लिए गम्भीर नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में 21 और झारखंड में 12 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच सकीं। जो विधानसभा की कुल संख्या के हिसाब से कम हैं।

योगी आदित्यनाथ के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ नारे के बाद महिला धन योजना ने महाराष्ट्र में बहुसंख्यक वोटरों को महायुति और एनडीए के पक्ष में एकजुट होने को इस कदर प्रेरित किया कि महायुति के घटक अजित पवार की राकांपा और शिंदे द्वारा खड़े किए कुछ मुस्लिम उम्मीदवार भी इस लहर में जीत का सेहरा बांध गए। महाराष्ट्र के नतीजों के सार को गम्भीरता से समझें तो दिखता है कि बालासाहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़कर कांग्रेस व शरद पवार की राकांपा के साथ जाने वाले शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और बरसों से महाराष्ट्र की राजनीति धुरी रहे शरद पवार के नेतृत्व की चमक को इस हार ने बहुत फीका कर दिया है। छह दशक से अधिक के सफल राजनीतिक जीवन में 84 बरस के शरद पवार के लिए ये हार सबसे शर्मनाक है।शरद पवार को उन्हीं अजित पवार ने पटखनी दी है जिनको उन्हीं ने राजनीति की एबीसीडी सिखाई। चुनावी नतीजों ने अब महाराष्ट्र में असली व नकली शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस की बहस को बेमानी करार दे दिया है।दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों ने बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। धुर्वीकरण को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है।

लेकिन ये भी देखना होगा कि अजित पवार और शिंदे के मुस्लिम उम्मीदवार भी सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व,राष्ट्वाद के सामने राहुल गांधी का संविधान बचाने’ का मुद्दा उस ‘काठ की हांडी’ की तरह साबित हुआ,जो विस चुनाव के चूल्हे पर नहीं चढ़ सकी। हरियाणा और महाराष्ट्र जीत कर मोदी ने फिर ये साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में आज भी उनका चेहरा विपक्ष के हर दांव पर भारी है।बहरहाल इन नतीजों के बाद शरद पवार,उद्धव ठाकरे, अखिलेश के साथ साथ कांग्रेस को भी अपने वजूद को टिकाए रखने की लड़ाई नए सिरे से लड़नी पड़ेगी और गठबंधन के महत्व को भी समझना होगा।

अमित कोहली
स्वतंत्र लेखक

मध्य-पूर्व में मौत का तांडव

इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष एक जटिल और गहन इतिहास पर आधारित है, जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में शुरू होता है।

इस संघर्ष की जड़ें कई महत्वपूर्ण घटनाओं और ऐतिहासिक परिवर्तनों में निहित हैं। 19वीं सदी के अंत और 20 वीं सदी की शुरुआत में ‘यहूदी पुर्नस्थापन आन्दोलन’ (झिओनिज्म) ने जन्म लिया, जिसका उद्देश्य यहूदियों के लिए एक राष्ट्र और पितृभूमि की स्थापना करना था। यह आन्दोलन 1897 में थियोडोर हर्ज़ल द्वारा आयोजित प्रथम यहूदी कांग्रेस के साथ आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। यहूदियों ने अपने ऐतिहासिक और धार्मिक सम्बन्धों के आधार पर फिलिस्तीन की भूमि पर दावा किया, जिसे वे अपनी प्राचीन पितृभूमि मानते थे। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 1917 में, ब्रिटिश सरकार ने ‘बेल्फोर घोषणा’ जारी की, जिसमें यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्र की स्थापना का समर्थन किया गया। इस घोषणा ने अरबों के बीच व्यापक असन्तोष उत्पन्न किया, जिन्होंने इस भूमि को अपनी मातृभूमि के रूप में देखा और यहूदियों के बढ़ते दखल की निन्दा की। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ‘लीग ऑफ नेशंस’ ने फिलिस्तीन को ‘ब्रिटिश मैण्डेट’ के रूप में सौंपा। इस अवधि में ‘झिओनिज्म’ ने गति पकड़ी और यहूदियों की संख्या में वृद्धि हुई। फलस्वरूप, अरब-यहूदी तनाव बढ़ने लगा और दोनों समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष होने लगे। 1929 और 1936-1939 के ‘अरब विद्रोह’ इसी तनाव का परिणाम थे, जिसमें कई लोग मारे गए और समुदायों के बीच दरार बढ़ी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 1947 में, ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ ने फिलिस्तीन को दो राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा - एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। यह योजना यहूदियों द्वारा स्वीकार की गई, लेकिन अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया। 14 मई 1948 को इज़रायल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप अरब-इज़रायल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में इज़रायल ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और लगभग 750,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए, जिसे ‘नाकबा’ (आपदा) के नाम से जाना जाता है। 1967 में हुए छह दिवसीय युद्ध में, इज़रायल ने ‘वेस्ट बैंक,’ ‘गज़ा पट्टी’ और पूर्वी येरुशलम पर कब्ज़ा कर लिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप, फिलिस्तीनी लोगों के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई। इस कब्जे के बाद, इज़रायल ने ‘वेस्ट बैंक’ और ‘गज़ा पट्टी’ में यहूदी बस्तियों का निर्माण शुरू किया जिससे और अधिक तनाव और हिंसा उत्पन्न हुई। 1987 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में असंतोष ने ‘प्रथम इंतिफादा’ (विद्रोह) का रूप लिया। इस विद्रोह में फिलिस्तीनी नागरिकों ने इज़रायली कब्ज़े के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध किया। ‘इंतिफादा’ ने वैश्विक समुदाय का ध्यान फिलिस्तीनी मुद्दों की ओर खींचा और इस्राइल और फिलिस्तीनी नेताओं के बीच बातचीत की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। 1993 में ‘ओस्लो (नार्वे) समझौता’ एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को मान्यता दी और दो-राज्य समाधान की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। इस समझौते के तहत ‘फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण’ यानि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना हुई और ‘वेस्ट बैंक’ और ‘गज़ा पट्टी’ के कुछ हिस्सों में स्वशासन की शुरुआत हुई। हालाँकि, इस समझौते के बावजूद, हिंसा और संघर्ष जारी रहे और स्थायी शान्ति का सपना अधूरा ही रह गया।

वर्ष 2000 में ‘दूसरा इंतिफादा’ शुरू हुआ जो पहले से भी अधिक हिंसक था। इस विद्रोह के दौरान, हज़ारों लोग मारे गए और शान्ति प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हुआ। 2005 में इज़रायल ने ‘गज़ा पट्टी’ से अपनी सेना हटा ली, लेकिन ‘हमास’ के सत्ता में आने के बाद ‘गज़ा पट्टी’ पर कड़ी घेराबन्दी लगा दी गई। वर्तमान संघर्ष की जड़ें 2005 में ‘गज़ा’ से इज़रायली सेना की वापसी और 2006 में ‘हमास’ के सत्ता में आने के बाद की घटनाओं में हैं। ‘हमास’ जो एक फिलिस्तीनी इस्लामिक संगठन है और जिसे इज़रायल और कई पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, ने ‘गज़ा’ पर नियंत्रण प्राप्त किया। इसके बाद से, इज़रायल और ‘हमास’ के बीच कई संघर्ष और युद्ध हो चुके हैं, जिसमें हज़ारों नागरिकों की मौतें हुई हैं और अनगिनत लोग बेघर हुए हैं।

विभिन्न मंचों पर इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच शान्ति स्थापित करने के कई प्रयास किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रयास 1993 में ‘ओस्लो समझौता’ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को मान्यता दी थी और ‘द्विराष्ट्र समाधान’ की दिशा में काम करने का संकल्प लिया था। हालाँकि, यह प्रयास असफल रहा और संघर्ष जारी रहा। ‘संयुक्त राष्ट्र संघ,’ ‘यूरोपियन यूनियन’ और विभिन्न देशों ने शान्ति वार्ताओं और प्रयासों का समर्थन किया है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। संघर्ष की जटिलता, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ और राजनीतिक अस्थिरता ने शान्ति प्रक्रिया को बाधित किया है। फिलिस्तीनी जनता के दृष्टिकोण से इज़रायल के कार्य अन्यायपूर्ण और आक्रामक हैं। भूमि पर कब्ज़ा, अवैध बस्तियों का निर्माण और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन उनके लिए गम्भीर चिन्ताएँ हैं। ‘गज़ा पट्टी’ की घेराबन्दी ने वहाँ के लोगों के जीवन को अत्यन्त कठिन बना दिया है, जहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोज़गारी की उच्च दर है। ‘हमास’ और अन्य फिलिस्तीनी गुटों ने हथियारबन्द संघर्ष का रास्ता अपनाया है, लेकिन कई नागरिक इस्राइली नीतियों के खिलाफ शान्तिपूर्ण प्रतिरोध का समर्थन करते हैं। इज़रायली बमबारी और सैन्य कार्यवाहियों में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौतें और सम्पत्ति का विनाश जारी है, जो उनके लिए अन्याय और पीड़ा का प्रतीक है।

यासिर अराफात के नेतृत्व में ‘फिलिस्तीन मुक्ति संगठन’ (पीएलओ) फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आन्दोलन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। अराफात, जो अपने करिश्माई नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, ने ‘पीएलओ’ को एक मामूली प्रतिरोध समूह से एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक इकाई में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो फिलिस्तीनी स्वायत्तता और राज्य का समर्थन करता है। यासिर अराफात की शान्ति के प्रति प्रतिबद्धता उनकी इज़रायल के साथ संवाद करने और हिंसा को रोकने के प्रयासों में स्पष्ट थी। आंतरिक विरोध और विभिन्न गुटों से संदेह का सामना करने के बावजूद, अराफात ने संघर्ष के शान्तिपूर्ण समाधान का समर्थन किया। उनके नेतृत्व को फिलिस्तीनी आन्दोलन की एकता बनाए रखने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में काम करने के संतुलन के रूप में देखा जाता है। शान्ति की दिशा में यात्रा चुनौतियों और बाधाओं से भरी रही है। 1995 में इज़रायली प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन की हत्या, जो शान्ति प्रक्रिया में एक प्रमुख भागीदार थे, एक महत्वपूर्ण झटका था। इसके अतिरिक्त, अन्तिम समझौते तक पहुँचने में विफलता और ‘वेस्ट बैंक’ में इज़रायली बस्तियों का विस्तार प्रगति में अवरोध उत्पन्न करते रहे हैं। अराफात की विरासत एक जटिल इतिहास है, जो फिलिस्तीनी संघर्ष के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और स्थायी शान्ति प्राप्त करने में कठिनाइयों को दर्शाती है। 2004 में उनकी मृत्यु ने नेतृत्व में एक खालीपन पैदा किया, जिससे शान्ति प्रक्रिया को जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो गया। हालाँकि, ‘पीएलओ’ और बाद में फिलिस्तीनी नेतृत्व ने ‘द्विराष्ट्र समाधान’ की दिशा में काम जारी रखा है, बावजूद इसके कि संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता बनी हुई है। महात्मा गाँधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत इस संघर्ष में कारगर हो सकते हैं। स्थायी शान्ति की ओर इज़रायल और गाज़ा के बीच का संघर्ष जटिल और गहरा है, लेकिन महात्मा गाँधी के सिद्धान्त इस संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से, दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिन्ताओं को समझ सकते हैं और स्थायी शान्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। इस संघर्ष के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग भी आवश्यक है। ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ और अन्य वैश्विक संस्थानों को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि न्याय और शान्ति की स्थापना हो सके। अन्ततः, यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष मिलकर संवाद और सहयोग के माध्यम से इस संघर्ष को समाप्त करें और एक नई, सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हों। (सप्रेस)

मेरे लिए संवैधानिक मूल्य का अर्थ

अनुभव

निधि
लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं सभी से सिर्फ अपना नाम साझा करूं क्योंकि कभी-कभी लगता है उपनाम जानकर लोगों का व्यवहार ना बदल जाएं। कृपया अन्यथा ना लें, लेकिन आज की अपनी बात को रखने से पहले मेरा पूरा परिचय देना ज़रूरी लग रहा है।

सीहोर के एक ब्लॉक इछावर से लगभग 10 किलोमीटर आगे बावड़िया नाम का एक गांव है, जहां लगभग 7 पीढ़ियों से मेरा पूरा परिवार रहता है। मैं एक ठेठ ब्राह्मण परिवार से हूं, जिनकी रोज की आजीविका पूजापाठ, कर्मकांड पर निर्भर थी। हमारे गांव में आज भी ऊँच-नीच जैसी व्यवस्थाएं है और लोग उसका पालन करते है। मेरे पापा भी उसी समाज का हिस्सा रहे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, उन्हें किसी भी तरह की अनुचित व्यवस्थाओं या नियमों को पालते हुए, जिसमें इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचे। शायद यही कारण रहा कि बचपन से ही उन्होंने मुझे और मेरे भाई को भी ऐसी किसी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनने दिया।

पापा अपनी नौकरी के सिलसिले में हमेशा गाँव से बाहर रहे और हम भी। हमने भी दुनिया उनके हिसाब से ही देखी और समझी, जिसमें किसी तरह का भेदभाव या जातिगत अंतर हम महसूस नहीं कर पाए। पापा के ऑफिस के वो कार्यकर्ता जो हमें स्कूल लेकर आते-जाते थे, या जो काम करने हमारे घर आती थी, सभी से आदर से पेश आना, हमारे लिए पापा की पहली शर्त थी।

हमारा घर ऑफिस के कैंपस में ही था। पापा के ऑफिस के सभी साथी, उनके ऑफिस का वो परिवार, जो घर से दूर हमारे लिए भी एक परिवार था, जिसमें बड़ें, छोटे बुजुर्ग सभी की गरिमा का ध्यान रखा जाता था। साथ बैठना, साथ खाना बनाना और साथ खाना। हर धर्म के त्योहार की खुशियां सभी के साथ मिलकर मनाते। किसी भी परिवेश में हो हमने हर धर्म का सम्मान करना सीखा और ये सब करते हुए मैं समझ पाई कि इंसान की पहचान धर्म से नहीं कर्म से होती है।

वास्तव में कहूं तो, यह सब बहुत ही सहज तरीके से हो रहा था, जिसे मैं कभी उस दृष्टि से नहीं देख पाई जैसे अब देखने लगी हूं। मेरे परिवार में मुझे भी भाई के बराबर का दर्जा देना हो या हमारे विवाह जैसे फैसले में हमारी मर्जी होना, मुझे, मेरी मां, और भाभी सभी को हर पारिवारिक निर्णय में शामिल करना हो या अपनी हार कहने की आज़ादी होना; ये सब मैंने अनुभव किया है। विवाह के समय सामने वाले की जाति ना देखकर उनके गुणों को आधार बनाना हो, किसी की मदद करने के लिए उसकी जाति जाने बिना उसकी हर संभव मदद करना हो या किसी भी समुदाय के व्यक्ति का स्वागत एक सा करना और उसे बराबरी का दर्जा देते हुए उसके सम्मान की बात हो; ये सब मैंने अनुभव किया है। सालों से चली आ रही हमारे परिवार की रूढियां जैसे घूंघट करना, महावारी में रसोई में ना जाना, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना जैसे कितने ही मुद्दों पर मेरे पापा ने परिवार के खिलाफ़ जाकर आवाज़ उठाई और इसकी शुरुआत परिवार से ही की।

मैं नहीं जानती मेरे पापा ने किस आधार पर हमारे लिए इन मूल्यों का पालन करना सीखाया लेकिन इतना जरुर है कि ये मूल्य हमारे संविधान की प्रस्तावना से बहुत हद तक मेल खाते है। इसमें बंधुत्व, भाईचारा, समता-समानता, धर्मनिरपेक्षता, गरिमा, जैसे सभी मूल्य निहित है। इन मानव मूल्यों को जिन्हें मैंने खुद जिया है, मैं उनका उम्रभर अनुसरण करुंगी।

सोचने वाली बात ये है, कि मेरे पापा ने ना सिर्फ इस मूल्यों को अपनाया बल्कि हमें भी अपनाने के लिए प्रेरित किया। मेरा मानना है कि इतने रुढ़िवादी और कट्टर हिन्दू परिवार का हिस्सा होकर भी अगर वो कर सकते है, तो कोई भी कर सकता है। मैंने आज भी संविधान को इतना गहराई से नहीं पढ़ा है और ना ही मैं इसकी बहुत समझ रखती हूं लेकिन जितना भी पढ़ा है, यह कह सकती हूं कि हमारा संविधान भी निष्पक्ष होकर मानव मूल्यों को प्राथमिकता देता है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

प्रीतम लखवाल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

मास्टरजी का ‘मास्टर स्ट्रोक’

वे मास्टरजी का नाम आते ही हमारे सामने पुराने जमाने की कवेलू वाली छत तनी स्कूल की तस्वीर घूम जाती है। उनकी छड़ी का स्मरण आते ही आज भी शरीर में कंपकंपी छूट जाती है। हथेली अपने आप को समेट लेती है और दर्द मिश्रित गुदगुदी होती है। आजकल तो मास्टरजी नाम को कोई जानता ही नहीं। मास्टर जी 21 वीं सदी में टीचर हो गए। 21 वीं सदी के गुजरे 24 साल में वे फ-टीचर हो गए। पहले शिक्षा प्राथमिकता होती थी। आज शिक्षा औपचारिक हो गई है और प्राथमिकता स्किल में बदल गई। आज भी सरकारी स्कूल में तो ‘मास्टरजी’ ही पढ़ाते आ रहे हैं, यहां उनका पद और रूतबा बदला नहीं है। उनकी मास्टरियत पर कोई शक ओ सुबहा नहीं है। मास्टरजी होने का मतलब सरकार का वो सब काम करने वाला, जिम्मा उठाने वाला जीव है, जो होता तो शिक्षा के लिए है, लेकिन उस पर जिम्मेदारियां किसी बाबू से कम नहीं है। वैसे सरकारी दफ्तर में बाबू नामक प्राणी भी होता है, लेकिन वह केवल नाम भर का होता है। बाबूगिरी से उसका कोई सरोकार नहीं होता। वह इससे आगे बढ़कर चमचागिरी तक पहुंच जाता है और अपने बॉस का खास होने की उपाधि प्राप्त कर पदोन्नति का अवार्ड ले लेता है और बाबू की कुर्सी को मुंह चिढ़ा देता है। बेचारे! मास्टरजी ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व इसलिए लिखना पड़ रहा है कि इससे उन्हें सम्मान की अनुभूति होती है और वे अपनी बहुविध प्रतिभा को हनुमान की याद कर अपने ओरिजनल स्वरूप को पहचाने में लग जाते हैं कि वे ‘मास्टर’ हैं। वे तो इतने कुशल हैं कि जरूरत पढ़ने पर वे इंसानों को गिन लेते हैं। गिनते भी आए हैं। वे जानवर भी गिनने की क्षमता रखते हैं। सरकार उनसे वे भी गिनवा लेती है और वोटों को गिनने और गिनवाने के मामले में तो उन्हें महारत ही हासिल है। उनके रहते मजाल है कि एक भी वोट इधर का उधर हो जाए। हालांकि, अब मत पेटी नहीं यांत्रिक पेटियां हैं, जिन्हें ‘एवीएम’ के अवतार के रूप में ‘जग ख्याति’ अर्जित है। वैसे अमेरिका, रूस और चीन जैसे संपन्नता के मद में इतराने वाले देशों में इन यांत्रिक मत पेटियों को कब की अंतिम विदाई दे दी गई है और श्रद्धांजलि सभाएं भी हो गई, लेकिन भारत में इसे ईमानदारी का ‘विश्व खिताब’ इसलिए मिला है कि यह बिगड़ती साख के बाद भी सरकार का ‘पहिया’ हिलने नहीं देती। आक्षेप तो इस पर खूब लगते हैं, लेकिन मजाल है कि यह अपने कर्तव्य से भटक जाए। जैसे मास्टर अपने कर्तव्य से नहीं डिगता।

एक दिन की बात है, कक्षा में पढ़ाते हुए मास्टर जी कसकलाल ने अपने विद्यार्थियों को बताया कि अब हमें नए भारत में ‘नया’ इतिहास पढ़ना होगा। चूंकि मास्टर कसकलाल इतिहास के ज्ञाता थे और उनका यह प्रिय सब्जेक्ट भी था, लेकिन उन्होंने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। वही पढ़ाया जो बहुत पहले से पढ़ाया जाता रहा और जिस किताब के पन्ने चूहों का ब्रेकफास्ट बन चुके थे और उनकी सन्तति जिनका लंच करने से भी जरा सा गुरेज नहीं करती है। कतरे हुए पन्ने से भी इतिहास पढ़ा देते हैं। खैर, वे इतिहास पढ़ाने में इतने निष्णात हैं कि उन्हीं की कही बात कई बार अखबार वाले अपने समाचारों में ‘कोड’ करते थे। इससे उन्हें इतनी तसल्ली मिलती कि चलो, उनकी बात पर किसी ने तो भरोसा किया। एक दिन स्कूल में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले मास्टरजी ने छुट्टी मार ली। अब प्राचार्य महाशय ने कसकलाल को अर्थशास्त्र पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी। वे अर्थशास्त्र के बारे में उतना ही जानते थे, जितना आम जनता अपने देश के बजट के बारे। फिर भी कसकलाल जी के मन में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने किताब खोले बगैर बच्चों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा दिया। वे इतना कह गए कि अगर आप लोग आत्मनिर्भर हो गए तो देश की अर्थ व्यवस्था विश्व की अग्रणी व्यवस्था बन जाएगी और हम पूरे विश्व में पूजे जाएंगे। मास्टर जी का यह मास्टर स्ट्रोक काम कर गया और बच्चों ने आत्मनिर्भर होने की ठान ली। मास्टरजी के इस ‘मास्टर स्ट्रोक’ की वजह से धीरे-धीरे क्लास खाली दिखने लगी। जब अर्थशास्त्र के मास्टर लौटे तो उन्होंने कसकलालजी से पूछ ही लिया कि ऐसा क्या पढ़ाया कि क्लास से बच्चे गायब रहने लगे। कसकलाल जी ने मुख पर मुस्कान लाते हुए कहा- मैंने बच्चों को वास्तविक अर्थशास्त्र का ‘अर्थ’ समझा दिया और वे उसी ‘अर्थ’ को कमाने में जुट गए होंगे। अर्थशास्त्र के मास्टर इस बात पर आग बबूला हो गए और बोले- ये क्या अनर्थ कर दिया। अभी बच्चों में अकल ही कितनी है। मास्टरजी कसकलाल ने कहा- जब सरकार के सिंहासन से ही आत्मनिर्भरता की धारा निकलने लगी हो तो हम और तुम उसे कैसे रोक सकते हैं भला। शिक्षा लेकर भी तो उन्हें लाइन में ही लगना है। अब अर्थशास्त्र के मास्टर को भी आत्मज्ञान हो गया और वे कसकलालजी से सहमति जताते हुए बोले- चलो कैंटिन में चलते हैं।

संविधान उत्सव

नरेंद्र सिंह तोमर

लेखक मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं।

जन-जन के सम्मान का प्रतीक हमारा संविधान

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार करते हुए भविष्य के भारत की विकास यात्रा के लिए जो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी राष्ट्र को परिभाषित करने वाले आधारभूत दस्तावेज को अंगीकार किया था, आज वह अपने अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है। यह समय है अपनी संवैधानिक व्यवस्था पर गर्व व्यक्त करने का। हमारा संविधान-हमारा सम्मान है।

संविधान को राष्ट्र को समर्पित करते हुए भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था 'संविधान महज वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम है और इसकी भावना सदैव युग की भावना है।' और यदि हम स्वतंत्र भारत में संवेधानिक प्रावधानों की महत्ता को देखें तो पाते हैं कि पिछले सात दशकों में, इसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित किया है - जो भारत के शासन के मूल सिद्धांत हैं।

हमारे संविधान का आधार स्तंभ इसकी प्रस्तावना है। हमारा संविधान ही प्रारंभ होता है - 'हम भारत के लोग' वाक्य के साथ, अर्थात् यहां मैं नहीं हम की भावना के साथ राष्ट्र का एक-एक जन, गणतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान की प्रस्तावना में ही जन कल्याण का ध्येय है और इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पूरी तरह से निहित है।

हमारे संविधान की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह जितना कठोर है उतना ही लचीला भी है। समय-समय पर काल, परिस्थितियों, राष्ट्र, जन कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए संविधान स्वयं में संशोधन की क्षमता रखता है। सितंबर 2024 तक हमारे संविधान में कुल 106 संशोधन हो चुके हैं और इन संशोधनों ने संविधान की शक्ति को ओर अधिक बढ़ाने का कार्य ही किया है।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में विगत दस वर्षों में सरकार ने संविधान में पूर्ण निष्ठा के साथ जन कल्याण की दिशा में तीव्र गति से कार्य किया है। यह दशक संविधान के लोकहित में सशक्त होने का समय था। संविधान में इस दौरान किए गए संशोधन न केवल ऐतिहासिक है अपितु राष्ट्र की प्रगति एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को गति प्रदान करने वाले भी रहे हैं।

संविधान का 106 वां संशोधन, इस देश की आधी आबादी अर्थात् नारी शक्ति के सशक्तिकरण को समर्पित है। दशकों से लंबित महिलाओं के हक की एक मांग को श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से साकार किया है। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण भारत में महिला नेतृत्व को एक नया आयाम देता है।

5 अगस्त 2019 को संविधान में हुआ संशोधन

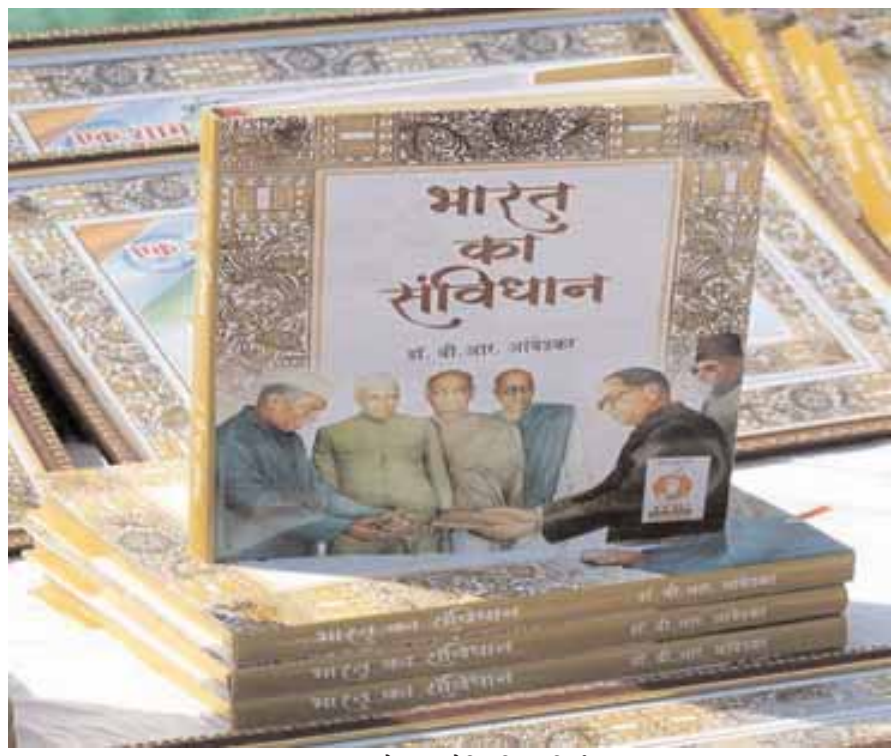

स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माना जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए संविधान में प्रावधानित अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाए जाने से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ' एक देश, एक विधान, एक प्रधान' का संकल्प स्वतंत्रता के 70 वर्ष उपरांत पूर्ण हो पाया। यह श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ निर्णय शक्ति का ही परिणाम है कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वलो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भी देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं।

तीन आपराधिक क़ानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू करके भारत सरकार ने दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारा है। अंग्रेजों के समय के कानूनों को समाप्त करके उनके स्थान नए नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से समकालीन चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने और लोक आशाओं को ज्यादा पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चिंतन में सदैव पहली प्राथमिकता कमजोर वर्ग को सशक्त कर उसे समाज की मुख्य धारा मे लाने की रही है। संविधान के 103 वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 2019 में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के कमजोर आर्थिक वर्ग वाले परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण में मील का पत्थर है।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने भारतीय मुस्लिम बहनों के जीवन में रोशनी का एक नया सूरज उगाया है। तीन तलाक जैसी कुप्रथा के अंत से मुस्लिम महिलाओं को अब समाज में बराबरी का अधिकार मिला है। संविधान में यह संशोधन मोदी की दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रतीक है । इसके साथ ही जीएसटी के माध्यम से एक देश एक कर की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान का 101 वां संशोधन, वर्ष 2019 में संविधान के 104 वें संशोधन के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था को 10 वर्ष और बढ़ाने जैसे कदम सरकार की जन कल्याण और प्रगति में गहरी निष्ठा को स्थापित करते हैं।

7 जून 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी-3 सरकार की शुरूआत करते हुए संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान की पवित्र पुस्तक को माथे से लगाकर नमन किया था। यही दृश्य पांच साल पहले मोदी-2 के समय भी दृष्टिगत हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की भारतीय संविधान में आस्था न केवल इन दृश्यों से अपितु उनके हर निर्णय से स्वतः परिलक्षित हो रही है। हम सभी को देश के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य पालन में संविधान के प्रति आस्था रखते हुए कार्य करना चाहिए। हमें सदैव अपने कर्तव्य का पालन और अधिकारों का यथोचित उपयोग करना चाहिए।

अमृतकाल में विकसित भारत की ओर अग्रसर हमारे राष्ट्र को हमारे संवैधानिक मूल्य सशक्त और समृद्ध करते हैं।

संविधान दिवस पर विशेष

चेतनादित्य आलोक

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार एवं राजनीतिक विश्लेषक है।

'मधुशाला' को लिखकर अमर हो गए बच्चन जी

हिंदी साहित्य के उत्तर छायावाद काल के कवियों में हरिवंश राय 'बच्चन' (27 नवंबर 1907-18 जनवरी 2003)को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हालांकि, बच्चन जी ने न केवल श्रेष्ठ कविताएं लिखकर पाठकों का मन मोहा, बल्कि अपनी गद्यात्मक रचनाओं के माध्यम से भी देशवासियों को अपना प्रशंसक बना लिया था। अपने दौर में कवि सम्मेलनों के सिरमौर माने जाने वाले बच्चन जी का आरंभिक जीवन संघर्षोंऔर चुनौतियोंसे भरा हुआ था। किशोरावस्था में पहुंचते ही उन्होंने परिवार के कई लोगों को खो दिया, जिनमें उनकी पहली पत्नी श्यामा जी भी शामिल थीं। बता दें कि बच्चन जी ने दो विवाह किए थे। उनकी पहली शादी श्यामा नामक युवती के साथ सन् 1926 में महज 19 वर्ष की आयु में ही कर दी गई थी। दुर्भाग्य से, श्यामा जी लंबे समय तक पति का साथ नहीं निभा पाईं। क्षय रोग से भीषण संघर्ष के बाद अंततः 1936 में उन्होंने प्राण त्याग दिया। पत्नी की असमय मृत्यु के बाद बच्चन जी बिल्कुल अकेले पड़ गए। इससे उनके कोमल मन-मस्तिष्क को गहराआघात सहना पड़ा और वे अवसाद के शिकार हो गए। पत्नी श्यामा देवी की बीमारी और फिर उनकी मृत्यु के कठिन दौर की मानसिक हलचल और उधेड़-बून को कविवर बच्चन ने अपनी आत्मकथा के प्रथम खंड 'क्या भूलूं क्या याद करूं' में बड़ी ही सहजता और बेबाकी से लिखा है। इसकी कुछ प्रसिद्ध लोकप्रिय पंक्तियां इस प्रकार हैं- 'क्या भूलूं क्या याद करूं मैं/ अगणित उन्मादों के क्षण हैं/ अगणित अवसादों के क्षण हैं/ रजनी की सूनी घड़ियों को/ किन-किन से आबाद करूं मैं/ क्या भूलूं क्या याद करूं मै...'

डॉ धर्मवीर भारती ने बच्चन जी की इस बेबाक और सहज शैली से प्रभावित होकर कहा था कि बच्चन हिंदी के हजार वर्षों के इतिहास में पहले ऐसे कवि और साहित्यकार हैं, जो अपने बारे में सबकुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से बयां कर देते हों। इसी प्रकार डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्वीकार किया है कि बच्चन की 'क्या भूलूं क्या याद करूं' नामक पुस्तक में केवल उनका परिवार और व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि उसमें उनका समूचा काल और क्षेत्र भी गहरे रंगों में उभरकर आया है। देखा जाए तो एक कवि और साहित्यकार की व्यथा का उसकी रचनाओं में उभरकर आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन बच्चन जी जैसे बड़े कद के कवि और साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा में जितनी उदारता दिखाई है, वह सचमुच उल्लेखनीय और सराहनीय है। हालांकि, जीवन में परस्पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बच्चन जी के आचरण और व्यवहार में भले ही भाव विह्वलता ने आश्रय पाई हो, लेकिन उन्होंने कर्म की अपनी पूंजी को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर परिस्थिति में हमेशा ही उनकी कर्मठता अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय बनी रही। दरअसल, चरम दुख की घड़ी से उबरने के लिए बच्चन जी ने अपनी लेखनी को ही अपना साथी और सहारा बना लिया था, जिसने न केवल उन्हें अवसाद की गहरी खाई में डूबने से बचाया, बल्कि उससे उबरने में भी सहायता की।

यही कारण है कि बच्चनजी की कई कविताएं घोर निराशा के क्षणों में भी आशा की किरण जगातीं और घुप्प अंधेरे में भी प्रकाश की राह पर ले जाती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसी ही उनकी 'जो बीत गई सो बात गई' शीर्षक कविताकी कुछ बेहद लोकप्रिय पंक्तियां इस प्रकार हैं- 'जीवन में एक सितारा था/ माना वह बेहद प्यारा था/ वह डूब गया तो डूब गया/ अम्बर के आनन को देखो/ कितने इसके तारे टूटे/ कितने इसके प्यारे छूटे/जो छूट गए फिर कहां मिले/पर बोलो टूटे तारों पर/ कब अम्बर शोक मनाता है/ जो बीत गई सो बात गई...'।

वैसे देखा जाए तो बच्चन जी की कविताओं में केवल संघर्ष, निराशा और आशा ही नहीं है। इसमें जीवंतता, उत्साह, उम्मीद, दृढ़ता और आत्मबल से परिपूर्ण स्वर भी भरपूर मौजूद हैं- 'अकेलेपन का बल पहचान/ शब्द कहां जो तुझको टोके/ हाथ कहां जो तुझको रोके/ राह वही है दिशा वही/ तू जिधर करे प्रस्थान/ अकेलेपन का बल पहचान...'।

वर्ष 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला स्थित बाबू पट्टी गांव में 27 नवंबर 1907 को जन्मेबच्चन जी के पिता का नाम लाला प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सुरसती देवी था।बता दें कि बच्चन जी का वास्तविक नाम हरिवंश श्रीवास्तव था, लेकिन बचपन में माता, पिता तथा परिवार के अन्य बड़ों के द्वारा 'बच्चन', जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है,कहकर बुलाए जाने के कारण

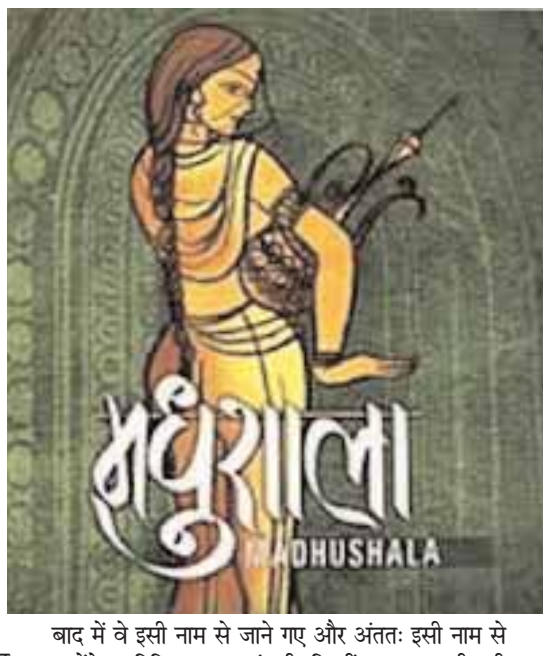

बाद में वे इसी नाम से जाने गए और अंततः इसी नाम से उन्होंने साहित्यिक रचनाएं भी लिखीं। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा-दीक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। बाद में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1941 से 1952 तक वे प्रयाग (तत्कालीन इलाहाबाद) विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे और आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र से जुड़कर भी अपना योगदान देते रहे। फिर अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि डब्ल्यू बी यीट्स की कविताओं पर शोध कार्य पूरा कर पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1955 में भारत लौटने के बाद विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ नियुक्त किए गए।

साहित्य शिल्पी बच्चन जी के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने बिल्कुल सीधी, सरल भाषा में साहित्यिक रचनाएंलिखीं।'आत्म परिचय'और'दिन जल्दी-जल्दी ढलता है' उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखा जाए तो 'दिन जल्दी जल्दी ढलता है'शीर्षक कविता में उन्होंने मानव जीवन की नश्वरता को स्वरदेते हुए अपने व्यक्तित्व के दार्शनिकपक्ष को उद्घाटित करने का सार्थक प्रयास किया है। वैसे, बच्चन जी मुख्यतः मनुष्य के मन, अनुभूति, प्राण तथा जीवन संघर्ष के उद्घोषक कवि हैं। एक ओर उनकी कविताओं में भावुकता के साथ-साथ रस और आनंदभरपूर मात्रा में विद्यमान है तो दूसरी ओर उनके गीतों में बौद्धिक संवेदना के साथ-साथ गहरी अनुभूतियां भी समाहित हैं। यह अकारण नहीं कहा जाता था कि कवि सम्मेलनों में कविवर बच्चन की कविताएं सुनकर श्रोता झूमने लगते थे। वैसे, देखा जाए तो विषय और शैली की दृष्टि से भी बच्चन जी की कविताएं विशेष हैं। दरअसल, उनकी कविताओं में समाहित स्वाभाविकता, रूमानियत, कसक, गेयता, सरलता और सरसता पाठकों को बांधकर रखने में सक्षम रही हैं। सच कहा जाए तो इन्हीं विशेषताओं के कारण बच्चन जी की रचनाओं को पाठकों के बीच काफी सराहा और पसंद किया गया।वैसे, बच्चन जी श्रोताओं और पाठकोंके लिएसहृदय होना जरूरी मानते थे।जाहिर है कि एक लेखक के रूप में वे अत्यंत भाग्यशाली रहे कि उन्हें हमेशा उनके मनोनुकूल सहृदयश्रोताओं औरपाठकों का साथ मिला।

कविवर 'बच्चन' की लोकप्रियता में उनकी सुमधुर भावनाओं से ओत-प्रोत काव्यकृति'मधुशाला' का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हालांकि,बच्चन जी की लोकप्रियता से ईर्ष्या रखने वाले भी कम लोग नहीं थे, जिनमें से कुछ ने तो एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ करने से रोकने के लिए गांधी जी से उनके विरूद्ध यह शिकायत कर दी थी कि आयोजकों ने एक ऐसे कवि को भी बुलाया है, जिसने मदिरा के गुणगान वाली पुस्तक 'मधुशाला' की रचना की है।उसके बाद गांधी जी ने बच्चन जी को बुलाकर 'मधुशाला' की कुछ पंक्तियां सुनाने के लिए कहा था। बच्चन जी ने तब 'मधुशाला' की कुछ पंक्तियां पढीं, जो इस प्रकार हैं-'मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला/ किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला-भाला/ अलग-अलग पथ बतलातेसब/ पर मैं ये बतलाता हूं-/ राह पकड़ तू एक चला चल/ पा जाएगा मधुशाला...'फिर बच्चन जी ने कुछ औरपंक्तियां पढीं- 'मुसलमान औ हिंदू हैं दो/ एक मगर उनका प्याला/ एक मगर उनका मदिरालय/ एक मगर उनकी हाला/ दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद-मंदिर में जाते/ बैर बढ़ाते मस्जिद-मंदिर मेल कराती मधुशाला...' मधुशाला की इन पंक्तियों को सुन कर गांधी जी ने बच्चन जी को आरोपों से लगभग मुक्त करते हुए तब कहा था- 'यह तो सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने वाली कविता है। जाइए, बेधड़क इसे सुनाइए।' हालांकि, गांधी जी से प्रमाण-पत्र मिल जाने के बावजूद बच्चन जी अपने ईर्ष्यालुआलोचकों के बाणों से कभी मुक्त नहीं हुए।

हालांकि,उनके समकालीन साहित्य के अधिकतर आलोचक उनकी मधुशाला की लोकप्रियता से दंग थे। उनका तो मानना यह था कि 'मधुशाला' के बाद यदि बच्चन जी कुछ और नहीं भी लिखें, तो भी उन्हें भुलाया नहीं जा सकेगा, किंतु यह हमारा सौभाग्य ही है कि वे 95 वर्ष से भी अधिक आयु तक जीवित रहे और लगातार प्रतिबद्ध होकर अपनी सृजनयात्रा करते रहे। यहां तक कि वर्ष 1966 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत होने के बाद भी उन्होंने लेखन से अवकाश नहीं लिया। मधुशाला की लोकप्रियता से जुड़ी कई वर्ष पहले की एक घटना याद आती है। एक बार साहित्य के कुछ विद्यार्थियों से मधुशाला के कुछ छंदों को सुनाकर उसके रचनाकार का नाम पूछने पर अधिकतर विद्यार्थियों ने कविता की पंक्तियां तो पहचान लीं, किंतु उसके रचनाकार का नाम अलग-अलग बताया था- रामधारी सिंह 'दिनकर', सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा औरहरिवंश राय 'बच्चन'। आश्चर्य, कि उनमें से एक-दो ने तो केवल इसलिए कविता की उन पंक्तियों को भी पहचानने से इंकार कर दिया था, क्योंकि उक्त कविता उनके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं थी। इसे विडंबना नही तो और क्या कहें कि साहित्य के विद्यार्थी केवल इसलिए बच्चन जी जैसे नामचीन कवि और उनकी लोकप्रिय रचना मधुशाला से अपरिचित रह जाते हैं, क्योंकि ये उनके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं।

गौरतलब है कि कविवर बच्चनफारसी के प्रसिद्ध कवि उमर खय्याम की रुबाइयों के हिंदी अनुवाद करने के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ आलोचकों का यह भी मानना रहा है कि उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना 'मधुशाला' पर उमर खय्याम की रुबाइयों का व्यापक प्रभाव पड़ा है। बहरहाल, मधुशाला की लोकप्रियता को देश और काल की सीमाएं भी बांधकर नहीं रख सकीं और देखते-ही-देखते बच्चन जी भारत भर के साहित्य प्रेमियों के दिलो-दिमाग पर ऐसे चढ़े कि फिर कभी उतरे ही नहीं। इसलिएयदि कहा जाए कि मधुशाला को लिखकर वे हिंदी की दुनिया में अमर हो गए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मुद्दा

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के पूर्व अधिकारी हैं।

जल जीवन मिशन योजना निजी हाथों में देने की तैयारी?

संविधान में आमजन को शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल उपलब्ध कराना सरकारों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किन्तु मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निजी हाथों में देने की तैयारी के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों की नल से जल योजना भी निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है ? इसके लिए तर्क यह दिया जा रहा है कि पंचायतें अपनी पंचायतों में हर घर में नल से जल देने की योजना में असफल सिद्ध हो गई है। उनके पास न बजट है, न संसाधन। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने यह प्रस्ताव बनाया है कि हर घर में नल से जल देने की योजना को अब निजी हाथों मे सौंप दिया जाए।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में 51 सिविल अस्पताल है। 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इनमें से प्रथम चरण में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने पीपीपी मोड पर 10 जिला अस्पतालों में निजी मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला कर लिया है। ये 10 जिला अस्पताल हैं- खरगोन, धार, बैतूल, टीकमगढ़, बालाघाट, कटनी, सीधी, भिंड, मुरैना आदि। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थान निजी हाथों में सौंपकर लोगों के स्वास्थ्य से समझौता कर रही है। मध्यप्रदेश के गरीबों के लिए बीमार होने पर एक मात्र सहारा सरकारी जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ही हैं। इन सरकारी अस्पतालों का भी निजीकरण कर दिया जाएगा तो गरीब अपना इलाज कराने कहाँ जायेगा ?

मध्यप्रदेश सरकार अब स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की तैयारियों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को भी निजी हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ छुड़ाना चाहती है। खास बात यह है कि यह योजना केन्द्र सरकार की है। केन्द्र सरकार देशभर में इस महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंर्तगत एकल ग्राम में हर घर नल से जल योजना संचालित कर रही है। अभी नल जल योजना की व्यवस्था का काम पंचायतों के हाथों में हैं। इसे पीएचई विभाग निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह वह यह बता रहा है कि ग्राम पंचायतें इस योजना को चलाने में असफल सिद्ध हो रही है। विभाग का प्रस्ताव यह है कि 100 गाँवों का एक क्लस्टर बनाकर एक निविदा आमंत्रित की जायेगी। 3 साल का ठेका दिया जायेगा। इसे 2 साल और बढ़ाया जा सकेगा।

पिछले दिनों उच्च स्तर की बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने यह प्रस्ताव रखा है कि नल से जल योजना का संचालन और संधारण का काम ठेके पर दे दिया जाए। बाहरी ऑपरेटर ही नल जल योजना का संचालन और मरम्मत आदि करें। विभाग ने इसके लिए यह भी तर्क दिया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह योजना 4 साल में बंद होने की कगार पर पहुँच जायेगी।

विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को सौंपते हुए 1100 करोड़ रूपए की माँग भी की है। इसके साथ ही वर्तमान में चल रही 12,500 एकल ग्राम योजनाओं में से 6500 गाँवों की योजनाओं के पुनः मूल्यांकन की जरूरत भी बताई है। इसमें लागत 3,200 करोड़ रूपए बढ़ने की संभावना भी बताई गई है।

केन्द्र सरकार की इस महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिन गाँवों को हर घर जल घोषित किया गया है, उनके संचालन का जिम्मा अभी पंचायतों के पास है। पीएचई विभाग का यह मानना है कि बजट और संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश गाँवों में रोज पानी वितरण भी नहीं हो पा रहा है। मध्यप्रदेश में 27,150 एकल ग्राम नल जल योजनाओं के लिए 17,911 करोड़ की राशि भी स्वीकृत है। इनमें से 12,500 योजना पूरी हो चुकी है। इस योजना में अभी तक मध्यप्रदेश में 52.50 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवारों से हर माह 60 रूपए की दर से बिल वसूल किए जाने का भी प्रावधान है। इस प्रकार विभाग को हर साल में 378 करोड़ रूपए मिलना चाहिए। किन्तु पिछले 3 साल में हर साल औसत 4.68 करोड़ रूपए ही मिले है।

पीएचई विभाग ने कम राशि मिलने पर भी पंचायतों से अधिकार लेकर यह योजना ठेके पर देने का प्रस्ताव किया है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2019 में पूरे देश के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया था। इसके लिए देश के हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक नल कनेक्शन से पेयजल प्रदान करने की योजना बनाई गई थी। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार का खर्च आधा-आधा रहता है। विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि देश में अब तक 78.96 प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन मिल चुका है। मध्यप्रदेश में इस योजना के अर्न्तगत 66.14 प्रतिशत घरों को कनेक्शन दे दिए गए हैं।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को व्यापक अधिकार देने की जोर-शोर से बात तो की जाती है, किन्तु जब भी मौका मिलता है पंचायतों के अधिकारों में कटौती करने से अधिकारी बाज नहीं आते हैं। यदि केन्द्र की इस महत्वपूर्ण योजना को ठेके पर दे दिया जायेगा तो यह माना जायेगा कि मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीणजन को पेयजल सुविधा देने की अपनी जिम्मेदारी से मुह मोड़ रही है। यह कदापि नहीं होना चाहिए। यदि पंचायतों को दिए गए अधिकारों का वे भंलीभाँत क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके कारणों की खोज खबर ली जाने की आवश्यकता है। समस्या की जड़ में जाने की जरूरत है। और उस समस्या को दूर करने महती आवश्यकता है। ना कि पंचायतों से उसका अधिकार छीनकर पेयजल का कार्य ठेके पर दे दिया जाए। आश्चर्य की बात यह भी है कि जनप्रतिनिधि भी इस मामले में चुप हैं। उन्हें मुखर होने की आवश्यकता है। भले ही वह किसी भी पार्टी के हों। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अपेक्षा है कि वे इस प्रस्तावित योजना पर रोक लगायंगे और पंचायतों को पर्याप्त बजट और संसाधन देकर उन्हें सक्षम बनायेंगे, ताकि वे दक्षतापूर्वक केन्द्र की इस महत्वपूर्ण योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर सकें।

पहली बार संभागीय स्तर पर आयोजित होगी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, छोटे उद्यमियों को मिलेगा फायदा

एक हजार से अधिक उद्योगपति, व्यापारियों और कारोबारियों ने कराया पंजीयन

फाइल फोटो

संजय द्विवेदी, बैतूल। संभागीय मुख्यालय नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन होना है। संभाग स्तर पर पहली बार यह आयोजन होने से जिले की छोटी इंडस्ट्री को भी अपना प्रदर्शन करने का बेहतर अवसर मिलेगा तथा उन्हें फायदा होगा। पहले सिर्फ मेट्रो सिटी में ग्लोब या राज्य स्तर की इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन होता रहा है। लेकिन मध्यप्रदेश में पहली बार संभाग स्तर पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। जिसमें बैतूल जिले से बड़ी संख्या में उद्योगपति, व्यापारी शामिल होंगे और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन को लेकर बैतूल के कारोबारियों में खासा उत्साह है। खनिज विभाग के स्टोन क्रेशर संचालक, स्वरोजगार योजना के उद्यमी, कृषि विभाग से जुड़े उत्पादों के कारोबारी, राइस व मैदा मिल संचालक, बड़े किसान, वेयरहाउस संचालक, जिले के रजिस्टर्ड स्टार्ट अप, नए निवेशक, वन विभाग के आरा मिल और फर्नीचर व्यापारी भी इससे जुड़ गए हैं। इन सेक्टरों से बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस तरह बैतूल में औद्योगिक निवेश बढ़ने और जिले का औद्योगिक विकास होने की संभावनाएं बन गई हैं। गौरतलब रहे कि कार्यक्रम में बैतूल जिले के हजारों उद्योगपति, व्यापारी और कारोबारी हिस्सा लेगे, जो एक अच्छा संकेत है। इससे भविष्य में जिले में उद्योगों में अधिक निवेश आने की संभावनाएं है।

एक हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन- रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के लिए बैतूल जिले से ही करीब एक हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए है। छोटे-बड़े सभी तरह के उद्योगपति और व्यवसायियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी मिलने के साथ ही संख्या भी तेजी से बढ़ती हुई एक हजार के पार निकल गई। बता दे कि औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होना है। जिसका उद्घाटन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्रों पर आधारित चार सत्र का आयोजन किया जायेगा तथा शिल्पकारों द्वारा उनकी शिल्पकला की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें बैतूल के उद्योगपति और कारोबारी अपनी इंडस्ट्रीज के स्टॉल लगाएंगे।

कॉन्क्लेव से मिलेगी है प्रेरणा और मौका- कॉन्क्लेव से नये लोगों को प्रेरणा और मौका मिलता है। इस कॉन्क्लेव में संभागीय स्तर पर आयोजन होने से बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले के ही उद्योगपति, व्यापारी और कारोबारी शामिल होगे। जिससे हर जिले के उद्योग और कारोबार को जानने का मौका मिलेगा। नये लोग अच्छेसे अपने अपना-अपना मत और उद्योग के बारे में जानकारी दे पायेगे। बैतूल जिले से अब तक जो पंजीयन हुए है उसमें प्रमुख रूप से स्वरोजगार योजना के उद्यमी, राइस मिल संचालक, निर्माण विभाग के कॉन्ट्रैक्टर, खनिज विभाग के स्टोन क्रेशर संचालक, कृषि विभाग से जुड़े उत्पादों के कारोबारी, वेयरहाउस संचालक, जिले के रजिस्टर्ड स्टार्टअप, नए निवेशक, वन विभाग के आरा मिल, फर्नीचर व्यापारी और जड़ी-बूटी के व्यापारी भी जाएंगे।

विलुप्त होती कला को उद्योग में विकसित करने का प्रयास

बैतूल शहर के बाहर बैतूल इटारसी फोरलेन से सटे टिगरिया क्राफ्ट विलेज के छह-सात शिल्पकार भी इस कॉनकेव में शामिल होगें। क्राफ्ट विलेज टिगरिया के शिल्पकार बलदेव बाघमारा ने बताया कि कॉन्क्लेव में जा रहे शिल्पकारों का प्रयास है कि जो हमारी विलुप्त होती कला को उद्योग के रूप में विकसित किया जा सके। इसके पहले भी हम लोग लघु उद्योग निगम की प्रदर्शनी में दिल्ली तथा अन्य मेट्रो सिटी में अपनी शिल्प कला की मूर्तियां का प्रदर्शन कर चुके हैं, जहां हमारी प्रदर्शनी को लोगों ने काफी सराहा और हमे कई पुरस्कार भी मिले। अभी हमारे साथी संदीप साकरे भी लघु उद्योग निगम की प्रदर्शनी में गए हुए हैं, वह भी विलुप्त होती कलाओं के उत्कृष्ट शिल्पकार हैं, उन्हें भी शासन द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। क्राफ्ट विलेज टिगरिया में बाँस के आइटम, जर-जरदोरी आइटम, लकड़ी के आइटम, भरेवा आइटम, सिर्फ जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर का परंपरागत शिल्प कला है और वर्तमान में विलुप्ति की कगार पर है, उसका काम किया जाता है। 7 दिसंबर को होने वाली नर्मदापुरम की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। जहां हमारा प्रयास होगा कि परंपरागत शिल्प कला को उद्योग का रूप दिया जा सके।

इनका कहना है -

रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के लिए बैतूल से करीब एक हजार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इससे औद्योगिक विकास के संकेत मिल रहे हैं। आसपास के जिलों में बैतूल पहला जिला है, जिसके रजिस्ट्रेशन एक हजार के पार गए हैं। हमारे द्वारा लगभग 500 हेक्टेयर जमीन जिले के उद्यमियों के लिए चिन्हित की गई है। इस कॉन्क्लेव में 6 सेक्टर पर फोकस रहेगा, जिनमें टूरिज्म, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, उद्यानकी, प्रौद्योगिकी और खनिज शामिल है। वन डिस्ट्रीक-वन प्रोडेक्ट के तहत सागौन लकड़ी को लेकर वुडन क्लस्टर बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 इंडस्ट्री लगाई जायेगी। इस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव बैतूल जिले के कॉफ्ट विलेज के शिल्पकारों के स्टॉल भी बतौर प्रदर्शनी लगाये जायेंगे। जिससे बैतूल की शिल्पकला का विकास हो सकेगा।

- रोहित डाबर, महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बैतूल

सट्टे के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही, दांव लिखते 6 धराए

बैतूल। पुलिस लगातार सटोरियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने 6 स्थानों पर दबिश देकर सट्टा लेखन में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों पर पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन. झारिया ने सटोरियों के विरुद्ध कठोर करने के निर्देश दिये थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी बैतूल सुश्री शालिनी परस्ते के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने सट्टा गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही की है। कोतवाली पुलिस की एक विशेष टीम का गठन कर नगर क्षेत्र में सट्टा गतिविधियों पर कार्यवाही के लिए रवाना किया गया। टीम द्वारा 6 स्थानों पर दबिश देकर सट्टा लेखन में लिप्त 6 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जिसमें सुनिल राजुरकर पिता गणपत राजुरकर, (32) निवासी शंकर नगर भग्गूढाना, राम शर्मा पिता चन्द्रकिशोर शर्मा (33) निवासी जवाहर वार्ड, गंज बैतूल, तुषार मालवीय पिता राकेश मालवीय (22) निवासी लोहिया वार्ड, गंज बैतूल, प्रयांशु पाली पिता पप्पू उर्फ राजेश पाली (21) निवासी दुर्गा वार्ड, खंजनपुर बैतूल, सुरेन्द्र ठाकुर पिता रूपसिंह ठाकुर (42) निवासी मोती वार्ड बैतूल और शैलेन्द्र पिता नारायण सिंह ठाकुर (38) निवासी माचना नगर गंज बैतूल को सट्टा पर्ची सहित कुल 7,610 रूपये नगदी के साथ पकड़ा गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रविकांत डेहरिया, उप निरीक्षक पंचम सिंह, उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद ठाकुर, आरकछक नितिन चौहान, प्र. आरक्षक अरविन्द, प्र. आरक्षक शुभम चौबे, महिला प्र. आरक्षक रंजना राजपूत एवं आरक्षक शिवकुमार की विशेष भूमिका रही।

खदान से केबल चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने केबल बरामद कर आरोपियों को भेजा जेल

बैतूल। सारणी पुलिस ने चोरी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 हजार रूपये का मशरूका बरामद किया है। आरोपियों ने डब्ल्यूसीएल खदान में चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर की रात्रि लगभग 3.30 बजे डब्ल्यूसीएल सारणी खदान से अज्ञात चोरों द्वारा इलेक्ट्रिक केबल (तार) चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसकी

शिकायत सारणी थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त चोरी में ओझाढाना बगडोना निवासी जामगिरी और उसके दो साथी शामिल हैं। पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ में मुख्य आरोपी जामगिरी पिता ज्ञानूगिरी (18) निवासी ओझाढाना ने अपने दो साथियों बंटी पिता अशोक पवार (35) निवासी पाथाखेड़ा और विकास पिता सुखराम धुर्वे (28) निवासी पाथाखेड़ा) के साथ मिलकर 50 मीटर इलेक्ट्रिक केबल चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से 15 मीटर केबल, जिसकी कीमत लगभग 12 हजार रुपये है, बरामद किया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल बैतूल भेज दिया गया। इस कार्रवाही में निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उप निरीक्षक वंशज श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक आसिफ खान, आरक्षक रविमोहन, सुभाष मंडलोई, सैनिक सुभाष रघुवंशी, हीरालाल पवार, और विनोद बरकड़े ने सराहनीय भूमिका निभाई।

सिलेंडर में लगी आग, तीन लोग झुलसे

बैतूल। घर में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। इस हादसे में पति, पत्नी और पिता बुरी तरह झुलस गए। तीनों को गंभीर हालत में मुलताई के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहां से बैतूल रेफर कर दिया गया। घटना मुलताई थाना क्षेत्र के आष्टा गांव में सोमवार शाम की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हादसे में लखन खातरकर (40 वर्ष), केशोराव खातरकर (63 वर्ष) और गीता पति लखन (35 वर्ष) सिलेंडर की आग से झुलसे हैं। जिस समय सिलेंडर में आग लगी, उस समय घर में बच्चे भी थे, लेकिन वे दूसरे कमरे में थे, इसलिए सुरक्षित बच गए। सिलेंडर की गैस खत्म हो जाने से आग अपने आप बुझ गई। यदि सिलेंडर में ज्यादा गैस होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पडोसी उमेश देशमुख ने बताया कि सभी की चीख-पुकार सुनकर वहां पहुंचे थे। वहीं घायल लखन ने बताया कि घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बन रहा था। इसी दौरान पास में रखे सिलेंडर में आग लग गई। जब वे सिलेंडर का रेगुलेटर निकालने पहुंचे तो वह भभक गई और उसकी चपेट में पत्नी और पिता भी आ गए।

मुलताई पहुंचे सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष वाजपेयी

बैतूल/मुलताई। रेलवे मजदूर संघ के होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है जिसको लेकर मंगलवार को मुंबई महाराष्ट्र सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष डॉ प्रेम बाजपेई पवित्र नगरी मुलताई स्टेशन पहुंचे। मजदूर संघ अध्यक्ष वाजपेई ने मुलताई पहुंचकर रेलवे कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और उन्हें ओल्ड पेंशन सहीत कर्मचारियों की अन्य समस्याओं को लेकर लड़ने का आश्वासन दिया। उन्होंने कर्मचारियों से कहा की एकजुट होकर संगठन को मजबूत करें और आने वाले चुनावों में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ को वोट करने की अपील की है। मुलताई स्टेशन पहुंचे मजदूर संघ अध्यक्ष के साथ वीरेंद्र सिंह नागपुर मंडल अध्यक्ष, राकेश कुमार मंडल सचिव, बीएस ताकसांडे, मंडल कोऑर्डिनेटर, संग्राम सिंह परिहार ,मंडल कोषाध्यक्ष, अभिजीत ठाकुर अध्यक्ष नागपुर एडमिन ब्रांच व गोपाल जी, बंडू रंधाई नागपुर से उपस्थित रहे। मुलताई से विके निरंजन ब्रांच सचिव एवं दीपक बारंगे डेलिकेट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ मुलताई ब्रांच सहित सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस असवर पर उन्होंने सदस्यों की समस्या भी सुनी और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया।

तालाब निर्माण से असिंचित क्षेत्र के किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा : खंडेलवाल

बैतूल विधायक ने एक करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

बैतूल। बैतूल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवगॉव के चौकी ग्राम में निवासरत आदिवासी किसानों को बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने बड़ी सौगात दी है। बैतूल विधायक के प्रयासों से मुख्यमंत्री विशेष निधी से चौकी ग्राम में 69 लाख 14 हजार रुपये की लागत से तालाब निर्माण स्वीकृत हुआ है। 26 नवंबर को बैतूल विधायक श्री खण्डेलवाल नें उक्त निर्माण कार्य का भूमिपूजन करने के बाद ग्रामीणों से संवाद के दौरान कहा कि तालाब निर्माण के बाद असिंचित क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी जिससे उनकी तरक्की की राह आसान हो जाएगी। बैतूल विधायक नें मुख्यमंत्री विशेष निधी से खेड़ीसावलीगंढ में पांढरी रोड पर नागदेव मंदिर के समीप पॉच लाख के सामुदायिक भवन,ग्राम पंचायत सराड में ग्राम कनारा से भट्टागिरी तक 20 लाख रुपये की 2 किमी ग्रेवल सडक तथा ग्राम पंचायत कुम्हली में 20 लाख रुपये लागत की दनोरा फोरलेन तक सीसी रोड नाली निर्माण एवं 19.96 लाख की 600 मीटर नाली निर्माण का भूमिपूजन किया।

हुनरमंद बनाकर रोजगार उपलब्ध कराएंगे

भूमिपूजन कार्यक्रमों में ग्रामीणों से संवाद के दौरान बैतूल विधायक श्री खंडेलवाल नें कहा कि जन जन की समस्याओं का त्वरित निराकरण एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानें के साथ ही उनका फोकस रोजगार पर है। उन्होनें कहा कि युवाओं और महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिलवाकर उन्हें हुनरमंद बनाकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए बैतूल जिले में बड़े उद्योगों और स्किल डव्हलपमेंट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करवानें के प्रयास किए जा रहे है। महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोडक़र आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। स्वरोजगार के लिए शहरी सहित ग्रामीण इलाकों में बड़े-छोटे शापिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे है। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे,जनपद सदस्य श्रीमति सरोज जितेन्द्र राठौर सहित ग्रामीण,अधिकारीगण मौजूद रहे।

खनिज मुरूम एवं गिट्टी का अवैध उत्खनन परिवहन करते पाए जाने पर 5 डंपर जब्त

बैतूल। खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही की है। सहायक खनिज अधिकारी एवं प्रभारी खनिज सर्वयर ने बताया कि 26 नवम्बर मंगलवार को बैतूल बाजार रोड पर खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुई 1 डम्पर क्रमांक MP04-HE-7037 को जप्त कर पुलिस थाना बैतूल बाजार की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। वहीं, मुलताई क्षेत्र में खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 03 डंपर क्रमांक क्रमशः MP48-H-1126, MH49-AT-7037, MP28-H-4295 को जप्त कर पुलिस थाना मुलताई में खड़ा किया गया है। खनिज निरीक्षक बैतूल द्वारा मुलताई क्षेत्र के अन्तर्गत दुनावा रोड पर खनिज अमले के साथ खनिज मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए 01 डम्पर क्रमांक MP 48 MB-0786 को जब्त कर खड़ा किया गया है। इसी प्रकार, मुलताई क्षेत्र अंतर्गत सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत कामथ द्वारा जनसुनवाई में शिकायत की थी कि ग्राम कामथ में खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन किया जा रहा हैं। जिसके बाद खनिज निरीक्षक ने स्थल की जांच की गई। जांच में ग्राम कामथ स्थित निजी भूमि खसरा क्रमांक 71/3 व 71/4 क्षेत्र पर भूमि स्वामी आशीष पिता लखनलाल डहारे द्वारा खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन कर खनिज का परिवहन किया जाना पाया गया। खनिज निरीक्षक द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया।

जेंडर आधारित हिंसा महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करती है

आंगनवाड़ी में मनाया गया संविधान दिवस

बैतूल/मुलताई। महिला एवं बाल विकास विभाग मुलताई द्वारा जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजागरूकता अभियान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत संविधान दिवस के

अवसर पर शास्त्री वार्ड आंगनवाड़ी केंद्र में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी उपस्थित जनों को संविधान की जानकारी दी गई एवं सभी को संविधान के पालन की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के माध्यम से यह बताया गया है कि जेंडर आधारित हिंसा शक्ति के असंतुलन पर आधारित होती है। लिंग आधारित हिंसा, महिलाओं और लड़कियों को ज़्यादा प्रभावित करती है, और जागरूकता के अभाव के चलते यह समाज में व्यापक विस्तार पा रही है। जब महिलाओं को जेंडर आधारित हिस्सा की रोकथाम के लिए बने कानूनो की जानकारी होगी और इस हिंसा के प्रकारों की समझ होगी तब ही जेंडर आधार हिंसा के रोकथाम के प्रयास सफल हो सकेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वार्ड वासी महिलाएं, महिला एवं बाल विकास परियोजना प्रभारी, गीता मालवीय एवं सरोज जगदेव पर्यवेक्षक मेडम उपस्थित थी इसके अलावा राजकुमार लोधे, बीसी रिंक यादव एवम सकु गलफट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रजनी परिहार, वंदना मौरे उपस्थित थी।

अवैध कब्जे संबंधी शिकायतों पर तत्काल कब्जा दिलाने के निर्देश

जनसुनवाई में आए आवेदनों का कलेक्टर ने किया निराकरण

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक सुनवाई कर उनका त्वरित निराकरण किया। जनसुनवाई में बैतूल निवासी गौरी जोजे ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उनके मकान को तोडक़र किसी अन्य को दे दिया गया है। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नगर पालिका के अमले को स्पॉट इंस्पेक्शन करने और शिकायत का परीक्षण कर कब्जा दिलाने के

निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। मुलताई निवासी आशीष रघुवंशी ने कलेक्टर को बताया कि उनकी भूमि के बंटवारे का प्रकरण बिना सूचना दिए ही निरस्त कर दिया गया। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने तहसीलदार मुलताई को आवेदक की गिरदावरी और बंटवारे की कार्यवाही शीघ्र कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में बैतूल की दीपका बाई ने नामांतरण का आवेदन बार-बार निरस्त किए जाने के संबंध में आवेदन दिया जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने एसडीएम और तहसीलदार बैतूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर आवेदक का तत्काल नामांतरण किए जाने के निर्देश दिए। सोना हिल्स कॉलोनी बैतूल के रहवासियों ने जनसुनवाई में बताया कि उनकी कॉलोनी के कॉलोनाइजर द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद सडक़ बिजली का पोल एवं नाली आदि मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने एसडीएम बैतूल को कॉलोनाइजर के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव शाहिद एन अधिकारियों द्वारा भी प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई की गई।

विचार

अनिल त्रिवेदी

अभिभाषक एवं स्वतंत्र लेखक

प्रकृति प्रदत्त वाणी एवं मनुष्य कृत भाषा

वाणी बुद्धि और विवेक के साथ ही सुनने की क्षमता अगर मनुष्य के पास न हो तो मनुष्य बोल ही नहीं पाता। वाणी होते हुए भी मनुष्य बोलना न चाहे या मौन रहना चाहे तो यह भी मनुष्य की अपनी प्राकृतिक शक्ति है। यही बात या ध्वनि सुनने को लेकर भी है। श्रवणेन्द्रिय सुनने के लिए है पर सुनना न सुनना यह मनुष्य की इच्छा पर है। आंखें देखने के लिए है जिसे हम दृष्टि की संज्ञा देते हैं पर इस देखने की क्षमता से अलग मनुष्य के पास एक अंतर्दृष्टि भी होती हैं जिसे मन की आंखों से देखा सोचा या प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि के लिए न तो प्रकाश की जरूरत होती है न आंखो की, केवल सोच समझ और कल्पना शक्ति से निराकार रूप से सारा कुछ सोचा समझा और मन-ही-मन प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। साकार बातें देखने के लिए इन्द्रियों की या ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता जरूरी है। पर निराकार कल्पना मन और बुद्धि का खेल है।

मनुष्यों को जन्म के साथ ही प्राकृतिक रूप से वाणी मिलती है। मनुष्येतर अन्य जीवों को भी वाणी तो किसी न किसी रूप में मिलती ही है पर मनुष्यों ने जिस रूप स्वरूप में वाणी द्वारा भाषाओं और संगीत को अपने जीवन को अभिव्यक्त करने वाले साधन के रूप में विस्तार दिया यह बिन्दु मानव सभ्यता के विकास और विस्तार का मूल है। मनुष्यों द्वारा अपने मुख से निकली ध्वनि के माध्यम से वाणी को विभिन्न भाषाओं में विकसित करना पृथ्वी के मनुष्यों का सबसे बड़ा सामूहिक कृतित्व ,पुरूषार्थ या पराक्रम माना जा सकता है। वाणी बुद्धि और विवेक के साथ ही सुननें की क्षमता अगर मनुष्य के पास न हो तो मनुष्य बोल ही नहीं पाता। वाणी होते हुए भी मनुष्य बोलना न चाहे या मौन रहना चाहे तो यह भी मनुष्य की अपनी प्राकृतिक शक्ति है। यही बात या ध्वनि सुनने को लेकर भी है। श्रवणेन्द्रिय सुनने के लिए है पर सुनना न सुनना यह मनुष्य की इच्छा पर है। आंखें देखने के लिए है जिसे हम दृष्टि की संज्ञा देते हैं पर इस देखने की क्षमता से अलग मनुष्य के पास एक अंतर्दृष्टि भी होती हैं जिसे मन की आंखों से देखा सोचा या प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि के लिए न तो प्रकाश की जरूरत होती है न आंखों की, केवल सोच समझ और कल्पना शक्ति से निराकार रूप से सारा कुछ सोचा समझा और मन-ही-मन प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। साकार बातें देखने के लिए इन्द्रियों की या ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता जरूरी है। पर निराकार कल्पना मन और बुद्धि का खेल है।

प्रकृति प्रदत्त ज्ञानेंद्रियों और मनुष्य की सृजनात्मक एवं

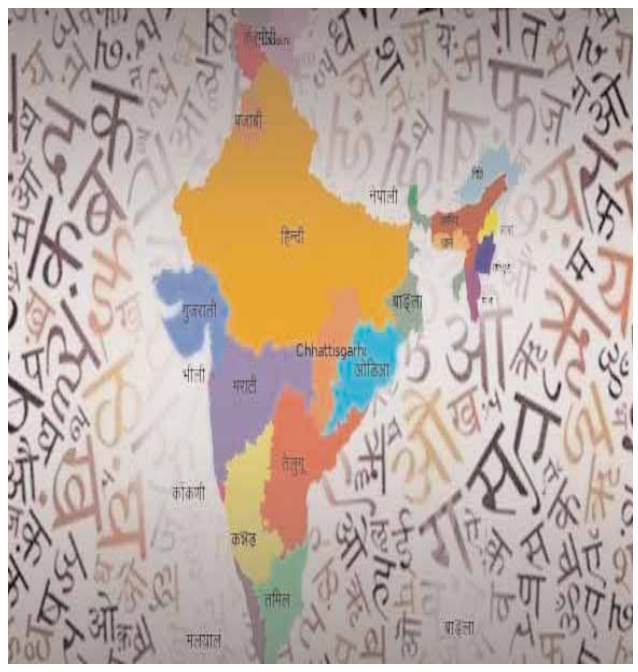

विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों की निरन्तर जुगलबंदी ने आज की दुनिया को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जहां तक पहुंच कर हम समूची सभ्यता की सृजनात्मक शक्ति बढ़ा और नष्ट-भ्रष्ट भी कर सकते हैं। हम अब वापस पुनः प्रागैतिहासिक सभ्यता में कोई एक व्यक्ति या समूचा मानव जगत भी नहीं पहुंच सकता। फिर भी आदिम से लेकर आज तक की कई सभ्यताएं एक साथ इस पृथ्वी पर कहीं-न-कहीं अपने मूल अस्तित्व को बचाए रखने का अंतहीन संघर्ष करती दिखाई पड़ सकती है। मनुष्य कृत सभ्यताओं की समूची कहानी मनुष्य के सोच विचार और कृतित्व का कमाल है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक और भविष्य में भी मनुष्य ने अपने जीवन में निरंतर बदलाव करते रहने की दिशा में निरंतर बढ़ते रहकर सृजनात्मक प्रवृत्तियों को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाया है। जो आज के और भविष्य के मनुष्य के सामने एक तरह से नित नयी चुनौतियों की तरह आ खड़ा हुआ है। पर मनुष्य को सृजनात्मक और विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों दोनों को अपनाने में शायद एक अलग तरह का आनंद आता है। निरंतर चुनौतियां सामने न हो तो मानव सभ्यता को आगे बढ़ने का अवसर ही न मिले यह सिद्धांत भी सामान्य रूप से माना जा सकता है।

मनुष्य की वाणी मूलतः ध्वनि के रूप में तो प्रायः एक समान ही प्रतीत होती है पर किस समय किस रूप स्वरूप और भाव के साथ वाणी का प्रयोग हुआ है यह वाणी का प्रयोग करने वाले और वाणी को सुनने वाले मनुष्य के मध्य वाणी के प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करता है। भाषा से अपरिचित अबोध बालक अपनी माता या पिता या अन्य निकटवर्ती मनुष्यों के भाव और आशय को समझने की प्राकृतिक क्षमता रखता है। यह समूचे मनुष्य जीवन या सभ्यता की अनौखी ज्ञान क्षमता है। तो क्या दृष्टि से मिलने वाले अबोध बालक के ज्ञान और समझ की क्षमताओं के विकास का मूल मनुष्य की देखने सुनने और समझने की क्षमताओं या प्रत्यक्षीकरण से प्रारंभ होती है? यह भी हमारे सोच समझ का एक महत्वपूर्ण आयाम है।

मानव सभ्यता में भाषाओं से ही समूची ज्ञान यात्रा का उदय हुआ और साहित्य संस्कृति और सृजनात्मक सभ्यता के अंतहीन आयामों का रूप स्वरूप मानव सभ्यता के स्थायी भाव बने। पर भाषा का ध्वनि स्वरूप और लिपि स्वरूप भी मानवीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। लिपि से जो ज्ञान यात्रा प्रारम्भ हुई उसने समाज को दो रूप स्वरूपों में विभाजित कर दिया । पढ़ें लिखे और बिना पढ़े लिखे। बिना पढ़े लिखे मनुष्य भाषा के ध्वनि स्वरूप को तो अच्छे से समझते जानते और बोलते हैं पर लिपि स्वरूप को नहीं जानते या पढ़ पाते। इस तरह ज्ञान की इस परम्परा में मानव समाज में पुनः एक भेद का उदय हुआ पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे या निरक्षर मनुष्य। ज्ञान मनुष्य समाज को निश्चित ही विकसित करने में मदद करता है पर अज्ञात और अज्ञान भी मनुष्य समाज को और अधिक खोजने की दिशा में प्रेरित करता है।ज्ञान अज्ञान और अज्ञात तीनों को ही समूची मानवीय सभ्यता की मूल आधारभूमि की तरह से ही समझा, सोचा और माना जाना चाहिए। मानव सभ्यता ज्ञानेंद्रियों और मनुष्य निर्मित अंतहीन विचारों की अनोखी श्रृंखला हैं जो साकार और निराकार जगत की चेतना से सदियों से मानव सभ्यता की तरंगों को आगे भी बढ़ा रहा है और कालक्रमानुसार लुप्त भी कर रहा है।

एम्स भोपाल में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रो. सिंह ने मिर्गी के दौरे से पहले दिखाई देने वाले संकेतों को पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी को दौरे से पहले असामान्य गंध या स्वाद महसूस हो, शरीर के किसी हिस्से में झनझनाहट या झटका महसूस हो, भ्रम की स्थिति हो, कमजोरी लगे, याददाश्त कमजोर हो, या सिरदर्द हो, तो तुरंत जांच करानी चाहिए। प्रो. सिंह ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए न्यूरोलॉजी विभाग की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल मिर्गी से जुड़े मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होती है। उन्होंने उपस्थित लोगों से इस जानकारी को अपनाने और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए तैयार रहने का आग्रह किया।

इस कार्यक्रम में मिर्गी और उसके लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, मिर्गी और मिर्गी के दौरे के दौरान क्या करना चाहिए, इस पर जागरूकता फैलाने के लिए एक पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को उनके रचनात्मक योगदान के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रो. शशांक पुरवार (कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक), डॉ. प्रियंका वी कश्यप और डॉ. अग्रता शर्मा, न्यूरोलॉजी विभाग, अन्य फैकल्टी सदस्य, रेजिडेंट्स, मरीज और उनके परिवारजन शामिल हुए।

एम्स भोपाल के डॉक्टर आईएसए 'ओएम' नेशनल अवॉर्ड 2024 से सम्मानित

भोपाल। एम्स भोपाल के ट्रॉमा और आपातकालीन चिकित्सा विभाग के सहायक प्रोफेसर, डॉ. सौरभ त्रिवेदी को आईएसए 'ओएम' (वन मिनट) नेशनल अवॉर्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट्स (आईएसए) के 71वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन, आईएसएसीओएन 2024 में अपने उत्कृष्ट शोध प्रस्तुतिकरण के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक, प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने डॉ. त्रिवेदी की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा, डॉ. सौरभ त्रिवेदी को आईएसएसीओएन 2024 जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिलना एम्स भोपाल की नवाचार और समर्पण की भावना का प्रतीक है। उनका यह कार्य मेडिकल पेशेवरों और शोधकर्ताओं को उत्कृष्टता की ओर निरंतर प्रयास करने और देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। डॉ. त्रिवेदी के पुरस्कार विजेता शोध का विषय 'ऐलन्स टेस्ट इन एन अनकॉन्शस पेशेंट-इज़ इट पॉसिबल' है। उनका यह अभिनव शोध आपातकालीन चिकित्सा और एनेस्थीसिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। यह सम्मान न केवल डॉ. त्रिवेदी के शैक्षणिक और चिकित्सकीय योगदान का प्रमाण है, बल्कि एम्स भोपाल की मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता को भी रेखांकित करता है।

एम्स भोपाल के डॉ. बी.एल. सोनी को एनएएमएससीओएन 2024 में अंगदान में नवाचार के लिए प्रथम पुरस्कार

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह संकाय और छात्रों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता और ज्ञान-साझाकरण की संस्कृति को सदैव बढ़ावा देते रहते हैं। प्रो. सिंह से प्रेरित होकर संकाय सदस्य विभिन्न शोध कार्यों में असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में, एम्स भोपाल के ट्रॉमा एवं आपातकालीन चिकित्सा विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. बी.एल. सोनी को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनएएमएससीओएन 2024) के 64वें वार्षिक सम्मेलन में मौखिक प्रस्तुति श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मेलन 21 से 24 नवंबर, 2024 के बीच एम्स जोधपुर में आयोजित किया गया, जिसमें देशभर से प्रतिष्ठित चिकित्सक और शोधकर्ता शामिल हुए। प्रो. सिंह ने इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, डॉ. सोनी का यह नवाचार अंगदान को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह दाताओं के सम्मान को बनाए रखते हुए लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करेगा और कई जिंदगियां बचाने में मदद करेगा। एम्स भोपाल ऐसे समाधान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो विज्ञान और मानवता के बीच एक सेतु का काम करें। डॉ. सोनी ने अंगदान के बाद हड्डी पुनर्निर्माण के लिए 3डी प्रिंटेड हड्डी समरूपों का नवाचारी उपयोग विषय पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने अंगदान से जुड़े जटिल मुद्दों के समाधान के लिए एक अनूठी तकनीक का प्रदर्शन किया।

कृषि मंत्री शिवराज का आभार

मंगलवार को प्रहलाद सिंह पटेल ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषित जनमन आवास योजना में मध्य प्रदेश ने एक मील का पत्थर हासिल किया है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूं और जब से वे मंत्री बने हैं, तब से लगभग 1.44 लाख आवास प्रदान किए गए हैं और अब आज मध्य प्रदेश को 33 हजार आवास प्रदान किए गए हैं।

डॉ. शर्मा बने जगन्नाथ मंदिर के ठाकुर राजा

राज्याभिषेक के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रारंभ

नर्मदापुरम। समीपस्थ ग्राम डोंगरवाडा में भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रथम दिवस मंगलवार शाम को आशुतोष शर्मा का ठाकुर राजा के रूप में अभिषेक किया गया। ओडिशा से आए विद्वानों ने समेरिटंस विद्यालय पहुंचकर मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक की विधि संपन्न की। इस दौरान ठाकुर राजा को वस्त्र, शस्त्र और आभूषण भेंट किए। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

विद्यालय में उत्सवी वातावरण- राज्याभिषेक विधि के दौरान विद्यालय में उत्सवी वातावरण रहा। विद्यालय परिसर को ध्वज, वंदनवार, तोरण, रंगोली आदि से सजाया गया था। परिसर के सरस्वती मंदिर में राज्याभिषेक की विधि संपन्न की गई। शंख और झालरों से विद्यालय गूंजता रहा। अंत में विद्वानों को राजा द्वारा वस्त्राभूषण भेंट करके विदा किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में जवा रोपण भी किया गया। कार्यक्रम में समिति के दिव्यजीत राय, अर्चक बाबाजी प्रसाद दास, प्रमोद शर्मा, अमित माहेश्वरी सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।

डा गौर को भारत रत्न दिए जाने की मांग, चलेगा अभियान

भोपाल। उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि डॉ. हरिसिंह गौर ने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज, जब पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है, ऐसे समय में डॉ. गौर की भव्य प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, वही सच्चे अर्थों में महापुरुष होता है। डॉ. गौर का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक है। वे ज्ञान, कर्म और भक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति विश्वविद्यालय की स्थापना में लगा दी, जिसका लाभ न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरे देश को मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा, सागर में भगवान के बाद यदि किसी की पूजा होती है तो वह डॉ. हरिसिंह गौर की। उन्होंने समाज को शिक्षा के माध्यम से प्रकाश प्रदान किया। उनका जीवन और योगदान सदा आदर और सम्मान के योग्य है। उप मुख्यमंत्री ने सागर के शनि मंदिर चौराहे पर डॉ. हरिसिंह गौर की प्रतिमा का अनावरण किया।

डॉ. गौर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिये जन-अभियान होगा प्रारंभ : मंत्री श्री राजपूत

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि डॉ. हरिसिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित के लिए जनमानस और प्रबुद्धजनों की मंशानुरूप जन-अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉ. गौर की मूर्ति उनकी संघर्षशीलता और जनकल्याण में योगदान के प्रति सम्मान का प्रकटीकरण है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय कभी पूरे भारत में चौथे स्थान पर था और आज भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हुए है।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निवास पर पहुंचे उप-मुख्यमंत्री

● सागर में डा गौर की प्रतिमा का किया अनावरण

भोपाल। सागर जिले के प्रभारी उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल डॉ.सर हरि सिंह गौर की जयंती के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए तत्पश्चात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निवास मातेश्वरी पहुंचे जहां उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल का मंत्री

गोविंद सिंह राजपूत एवं जिले भर से आये जनप्रतिनिधियों ने आत्मीयता एवं गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। श्री राजपूत के यहां स्नेह भोज में बुंदेली व्यंजनों परोसे गये। इस अवसर पर जिले भर से आये जन-प्रतिनिधियों ने उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल से डॉ. सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने को लेकर बिंदुबार चर्चा की। चर्चा में डॉ. सर हरि सिंह गौर के त्यार परिश्रम, बुंदेलखंड के लिए दिये गये विश्वविद्यालय आदि की जानकारी दी गई। जन प्रतिनिधियों ने कहा कि बुंदेलखंड सहित पूरे भारत के लिए उस समय खोला गया जब सागर में कलम दवाद भी नहीं मिलती थी। यह विश्वविद्यालय वरदान से कम नही हैं। जिसके लिए गौर साहब ने अपनी जीवन की सारी पूंजी दान कर दी थी। गौर साहब से सभी की भावनाएं जुड़ी हैं इसलिए गौर साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जावे। उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सभी जनप्रतिनिधियों को आश्वासन देते हुए कहा कि आप सभी इस बात के लिए आगे तक पहुंचायेंगे। हम सभी गौर साहब के लिए भारत रत्न दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने उप-मुख्यमंत्री का निज-निवास पर पधारने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, सांसद श्रीमति लंता बानखेड़े, सागर विधायक शैलेन्द्र जैन, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, बण्डा विधायक वीरेन्द्र सिंह लंबरदार, पूर्व विधायक सुधा जैन, पूर्व विधायक धरमू राय, पूर्व विधायक सिलारपुर, पूर्व विधायक भानू राणा, पूर्व विधायक श्रीमति पारूल साहू, पूर्व मंत्री नारायणप्रसाद कबीरपंथी, मप्र खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह मोकलपुर, निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार, पूर्व महापौर श्रीमति अनिता अहिरवार, डॉ. सुखदेव मिश्रा, डॉ. वीरेन्द्र पाठक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष एड देवेन्द्र ठाकुर, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष प्रदीप पाठक, एस.वी.एन.वि.वि. के कुलपति अनिल तिवारी, ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के कुलपति आदित्य सिंह राजपूत, देवेन्द्र कटारे, देवेन्द्र फुशकेले, कैलाश चौरसिया, शैलेष केशरवानी, भगत सिंह लोधी, अरविंद सिंह टिंकू राजा, अनिल पीपरा, सिद्धार्थ पचौरी, सहित जिले भर के प्रमुख जन उपस्थित रहे।

संविधान संवाद का आयोजन किया

भोपाल। संविधान दिवस के अवसर पर विकास संवाद एवं चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला, बोर्ड कॉलोनी, रविशंकर नगर, भोपाल में एक विशेष कार्यक्रम 'संविधान संवाद' का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बच्चों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अभिभावकों सहित लगभग 230 लोगों ने सक्रिय भागीदारी की।

कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की उद्देशिका के सामूहिक वाचन और सभी प्रतिभागियों द्वारा संवैधानिक मूल्यों के पालन की शपथ के साथ हुई।

बच्चों के साथ 'संविधान संवाद' सत्र में संविधान क्या है, इसका महत्व, और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई। इसमें मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। बच्चों ने वीडियो क्लिप्स के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों की जरूरत और उनके महत्व को समझा। इस दौरान बच्चों ने अपने अनुभव और आस-पास की घटनाओं को साझा करते हुए संविधान की प्रासंगिकता पर चर्चा की।

कार्यक्रम के अंत में संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी (क्विज़) का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी समझ का प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर विद्यालय की प्रधान अध्यापिका कविता वर्मा, शिक्षक दहाय, शिक्षिका राजश्री पाटीदार, ऊषा, और विकास संवाद भोपाल से राजेश भदौरिया, शिवराज कुशवाह एवं शिवकुमारी यादव उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अपने संवैधानिक मूल्यों की जानकारी प्राप्त करने और अपने जीवन में उनके महत्व को समझने का एक मंच मिला।

देश का संविधान ही धर्मग्रन्थ है : मंत्री सारंग

संविधान की प्रतिकृति को नमन कर शुरू हुई संविधान दिवस पदयात्रा

भोपाल। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि हमारे देश का संविधान ही धर्मग्रन्थ है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का साधुवाद करते हुए कहा कि सम्पूर्ण देश में आज संविधान दिवस पर पद यात्रा का आयोजन कर हम सबको प्रेरणा दी है कि लोकतंत्र में आज हम आजाद हिन्दुस्तानी के नाते जी रहे है। मंत्री श्री सारंग शौर्य स्मारक में संविधान दिवस पद यात्रा के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

शक्तिशाली हिन्दुस्तान बनाने का संकल्प- मंत्री श्री सारंग ने कहा कि वर्षों की गुलामी के बाद हजारों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद से हमें आजादी मिली है। आजादी के बाद किस व्यवस्था के तहत कार्य होगा। हमारा संविधान, नियम, कायदें क्या होंगे इसको लेकर गहन चिंतन हुआ और बाबा साहेब के नेतृत्व में संविधान सभा में संविधान बनाया गया। मंत्री श्री सारंग ने बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता और नमन करते हुए कहा कि उन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनाया। आज के ही दिन वर्ष 1949 में यह संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज हम सब संविधान भावनाओं को संकल्प के रूप में ग्रहण करके आजाद हिन्दुस्तान को शक्तिशाली हिन्दुस्तान बनाने के संकल्प के साथ पद यात्रा में शामिल हो रहे है। यह शौर्य स्मारक शूरवीर की शाहदत का प्रतीक है।

मंत्री श्री सारंग ने बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने को कहा। उन्होंने क्रांतिकारियों को नमन किया, जिन्होंने देश की आजादी के लिये अपना सर्वस्व निछावर किया। मंत्री श्री सारंग ने युवाओं का आहवान किया कि भारत माता के लिये पूरी सिद्दत के साथ उन्हीं

के लिये जीएंगे और जरूरत पड़ने पर तैयार रहेंगे। यह हिन्दुस्तान एक बार फिर विश्वगुरू के रूप में स्थापित हो। यहीं हमारा कर्तव्य ओर संकल्प है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का संदेश- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रिकार्डेड संदेश भी सुनवाया गया। साथ ही संविधान की प्रस्तावना का वाचन और राष्ट्रगान भी हुआ। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

संवैधानिक नैतिकता के साथ अपने कार्यों का करें पालन

राज्यपाल ने किया आव्हान, कहा-संविधान के संरक्षक हैं भारत के लोग

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने संविधान के अंगीकरण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेशवासियों का आवाहन किया है कि संविधान दिवस पर अपने सभी कार्यों में संवैधानिक नैतिकता के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सत्यनिष्ठा के साथ दोहराएं। संकल्प करे कि नागरिक अपने आचरण और व्यवहार से संविधान से प्राप्त अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों के पालन के लिए जन जागरूकता को बढ़ाने में सक्रिय योगदान देंगे। राज्यपाल श्री

● राज्यपाल संविधान प्रस्तावना के सामूहिक वाचन कार्यक्रम में हुए शामिल

पटेल राज्य शासन द्वारा आयोजित संविधान प्रस्तावना के सामूहिक वाचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजनेताओं, अधिकारियों और नागरिकों को हंस ध्वनि सभागार, रवीन्द्र भवन में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम में सहभागी जनों को संविधान प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा निर्मित वृत्त चित्र ग्लोरी ऑफ कंस्टीटूशन और प्रदेश के संसदीय कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि संविधान हम भारतीयों के लिए प्रेरणादायक जीवंत दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्मग्रंथ है, जो हम सबका मार्गदर्शक है। संविधान को देश के हर नागरिक ने अंगीकृत किया है, इसलिए संविधान के वास्तविक संरक्षक, हम भारत के लोग ही है। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक का नहीं, बल्कि सभी का संरक्षक है। इसलिए उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। संविधान, जहाँ एक ओर नागरिकों को सशक्त करता है, वहीं दूसरी ओर नागरिक भी अपने आचरण, व्यवहार से संविधान का समर्थन और संरक्षण करते है। इसलिए जरूरी है कि देश का प्रत्येक नागरिक समर्पित भाव से संविधान के उद्देश्यों, महत्व को समझे और समुचित पालन के द्वारा संविधान के प्रति अपने सम्मान का प्रदर्शन करे। देश के हर वर्ग, हर समुदाय और हर नागरिक का अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सजग और सक्रिय रहना आवश्यक है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व और विश्वव्यापी मूल्यों की समझ का अवसर और उत्सव है। इस महत्वपूर्ण प्रसंग को 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। जरूरी है कि संविधान निर्माताओं द्वारा स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और आत्म-निर्भर राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए लम्बे संघर्ष और त्याग के बारे में भावी पीढ़ी को परिचित कराया जाए। संविधान दिवस को केवल शासन और राजनैतिक दलों का उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माताओं के योगदान के प्रति आभार के उत्सव के रूप में मनाया जाए। हम सबका दायित्व है कि संविधान के अनुसार जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए बिना, एक सशक्त और समावेशी समाज बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। राज्यपाल श्री पटेल ने संविधान दिवस के पावन प्रसंग पर भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी महान व्यक्तित्वों का पुण्य स्मरण किया। उन्हंत नमन करते हुए कहा कि उनकी अद्भुत दूरदृष्टि और प्रयासों ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है, जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। इसके लिए हम सब उनके प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई दी।

संविधान हमारे देश की आत्मा का प्रतिबिम्ब है : देवड़ा

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारा संविधान कानूनों का संग्रह नहीं, हमारे देश की आत्मा का प्रतिबिम्ब है। 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' अभियान की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें स्वाधीन जीवन जीने का अधिकार देने के साथ ही स्वतंत्रता की सीमा भी बताई है। श्री देवड़ा कहा कि हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संविधान है जो सभी को समानता, स्वतंत्रता और न्याय उपलब्ध कराता है। उन्होंने संविधान के निर्माता विभूतियों डॉ अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए कहा कि संविधान के मूल्यों से भावी पीढ़ी को परिचित कराना, हम सबका दायित्व है। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि भारतीय इतिहास में संविधान को अंगीकृत करने का स्वर्णिम दिवस 26 नवंबर का दिन है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं के लगभग 3 वर्षों की कड़ी मेहनत से तैयार संविधान युगीन भावनाओं को प्रतिबिम्बित करने वाला सुदृढ़ जीवंत दस्तावेज है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों और बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मरण करते हुए, उन्हें नमन किया। राज्यपाल श्री पटेल सहित अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। अतिथियों का स्वागत पुष्प-गुच्छ भेंट कर किया गया। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग की राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक द्वय श्री रामेश्वर शर्मा, श्री भगवान दास सबनानी और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के.सी. गुप्ता मंचासीन थे।

मंत्री ने अजान सुनकर भाषण रोका, मंच पर पढ़ा कलमा

राजगढ़ में कहा-ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोले-सभी धर्मों का सम्मान करें

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार में राज्यमंत्री गौतम टेटवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान अजान की आवाज आने पर अपना भाषण रोक दिया। अजान खत्म होने पर उन्होंने कहा कि सब धर्मों का सम्मान करो। यही हमारी संस्कृति है। इसका वीडियो भी सामने आया है। मंत्री मंच से 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही इसका मतलब भी समझा रहे हैं। बाद में उन्होंने ये नसीहत भी दी है कि अगर हम

मुस्लिम धर्म का सम्मान करते हैं, तो वो भी गौमाता, गंगा, सनातन धर्म के मान बिंदू का सम्मान करें। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सारंगपुर विधायक गौतम टेटवाल का ये वीडियो रविवार का है, जो मंगलवार को सामने आया है। मंत्री राजगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मऊ पहुंचे थे। यहां उन्होंने निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। मंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शाम 7.15 बजे (ईशा) की अजान शुरू होने पर उन्होंने अपना भाषण बीच में रोक दिया। फिर मंच से ही कहा- उससे डरो, वह एक है। नेक काम करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संपूर्ण भूमि गोपाल की है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है। मंत्री ने आगे कहा- दुनिया में आए हो, तो सबका सम्मान करो। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबका कल्याण हो। यह बात वह भी कह रहा है, और हम भी कह रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या गलत कह रहा हूं? सनातन संस्कृति ऐसी है जिसमें सबका समावेश है।

हमारी संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे- मंत्री गौतम टेटवाल ने बाद में कहा-गौ माता का सम्मान करें। गंगा जी का सम्मान करें। सनातन हिंदू समाज के स्वाभिमान के मान बिंदु हैं, उनका सम्मान करें। हमारी उपासना पद्धति का सम्मान करें। अगर हम मुस्लिम धर्म का सम्मान करते हैं। अजान का हमने इसलिए सम्मान किया, ठीक है, अजान हो रही है, तुम पांच टाइम नमाज पढ़ों, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे मान बिंदु, हमारी संस्कृति के बिंदुओं को अपमानित करो। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। मंत्री ने कहा- सबका ईश्वर एक है। सभी नदियां और नाले मिलकर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, फिर भी उसमें पवित्रता होती है। इसी तरह ईश्वर एक है, इसी तरह सारे धर्म मिलकर सनातन धर्म में विलीन हो जाते हैं।

कांग्रेस बोली- इनकी कथनी और करनी में अंतर- राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंदर सिंह सोंधिया ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। आज संविधान दिवस है। हम सभी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। सब धर्मों का सम्मान हो, संविधान हमें यही सिखाता है। मंत्री टेटवाल ने यदि अजान के समय अपना भाषण रोका है तो यह स्वागत योग्य है। सभी भाजपाइयों से यही कहूंगा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करें। अजान के समय तो उन्होंने भाषण रोक दिया। कुछ समय बाद ही वे गोधरा कांड पर बनी साबरमती फिल्म देखने गए। उसी दिन हमने उनका दूसरा रूप भी देख लिया, जब जुलूस के रूप में आक्रोशित नारे लगाते हुए 500 से ज्यादा भाजपाइयों के साथ वे फिल्म देखने निकले। सोंधिया ने कहा- भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लाउडस्पीकर पर रोक लगाई है। यह उनकी सस्ती लोक प्रियता हासिल करने का तरीका है। भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। ये घोषणा तो कर देते हैं, जमीन पर कुछ होता नहीं है।

18 दुकानें तोड़ने की मोहलत खत्म, जेसीबी से तोड़ी

भोपाल मेट्रो के दूसरे फेज में आड़े आ रही 108 आरा मशीनें हटाने में देरी

भोपाल। भोपाल मेट्रो के दूसरे फेज में आड़े आ रही 18 पक्की दुकानों को तोड़ने की मोहलत खत्म हो गई और मंगलवार को जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से उन्हें हटा दिया। हालांकि, कार्रवाई से पहले ही दुकानदारों ने अपना सामान निकाल लिया। ताकि, नुकसान न हो। मेट्रो का दूसरा फेज सुभाष नगर डिपो से करोंद तक कुल 8.77 किमी है। यह काम भी दो हिस्से में होगा। दोनों पर कुल 1540 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मिट्टी की टेस्टिंग, डिजाइन समेत अन्य काम हो चुके हैं। अब अतिक्रमण हटाने पर फोकस है। ताकि, सिविल के काम जल्दी

शुरू हो सकें। शहर वृत्त एसडीएम दीपक पांडे ने बताया, पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। जिन दुकानदारों से शाम तक सामान हटाने की बात कहीं, उन्हें राहत दी गई। सामान हटाते ही जेसीबी की मदद से दुकानें तोड़ दी गई। बता दें कि सितंबर में पुल बोगदा और आजाद नगर में कुछ अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन पक्की दुकानों को हटाने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई थी। लोगों ने खुद अपनी दुकानें हटाने की सहमति दी थी, पर उन्होंने नहीं हटाई। इसलिए मंगलवार को प्रशासन खुद इन्हें तोड़ने वाला था, लेकिन इससे पहले लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। आजाद नगर में कुल 108 आरा मशीनें हैं, जो शिफ्ट नहीं हो पाई है। जिस जगह ये शिफ्ट होनी है, वहां पानी, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं नहीं है। इनके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने टेंडर कॉल किए हैं। ऐसे में अंडरग्राउंड लाइन के लिए मशीनें नहीं आ पा रही है। बता दें कि बरखेड़ी फाटक से भारत टॉकीज तक मेट्रो के रूट पर 108 आरा मशीनें हैं।

विजयपुर चुनाव हारने के बाद एमपी बीजेपी में कलह!

रामनिवास रावत ने उपचुनाव की हार के बाद लगाए गंभीर आरोप

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री राम निवास रावत विजयपुर उपचुनाव हार गए। उन्होंने अपनी हार के लिए भाजपा के अंदरूनी लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। इसने एक बार फिर एमपी बीजेपी में हो रहे अंतर्कलह को उजागर किया है। इसके बाद वन मंत्री रामनिवास रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रावत कांग्रेस से भाजपा में आए थे। उन्हें सिंधिया समर्थक माना जाता है। उनके लिए सिंधिया का प्रचार न करना भी हार का एक कारण बताया जा रहा है। रावत ने कांग्रेस पर आदिवासी गांव पर हमले का झूठा इल्ज़ाम लगाने का भी आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रावत के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने भाजपा के कुछ लोगों पर उनकी हार की साजिश रचने का आरोप लगाया। रावत ने कहा कि कुछ लोग उन्हें बीजेपी में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ काम किया। रावत ने कहा कि जनता ने उन्हें 93,000 वोट दिए। यह साबित करता है कि जनता उनके साथ है। लेकिन कुछ लोग उनके मंत्री बनने से खुश नहीं थे। रावत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को पूरी रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि कैसे कुछ लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया। रावत ने बताया कि कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को गुमराह किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर रावत जीत गए तो वह सिर्फ अपने समर्थकों का ध्यान रखेंगे। रावत ने कहा कि विजयपुर की जनता ने उन्हें नहीं हराया। बल्कि कुछ और लोग उनकी हार के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को लगा कि रावत के भाजपा में आने से उनका सब कुछ छिन जाएगा। रावत इस साल की शुरुआत में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें जुलाई में मंत्री बनाया गया था। विजयपुर को रावत का गढ़ माना जाता था। वे वहां से छह बार विधायक रह चुके हैं। इस बार कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने उन्हें 7,228 वोटों से हरा दिया।

रेलवे लाइन के विस्तार से प्रदेश के नागरिकों को मिलेगी बड़ी सुविधा

मुख्यमंत्री ने रेलवे की तीन मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी के लिए पीएम का माना आभार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रेल मंत्रालय की 7 हजार 927 करोड़ रुपये लागत की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व

में प्रदेश में रेलवे के बढ़ते नेटवर्क से प्रदेश विकास पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है, प्रदेशवासियों के लिए आवागमन भी तीव्र गति से सुगम हुआ है। प्रदेश को मिल रही नित नई सौगातों के लिए प्रदेशवासी प्रधानमंत्री श्री मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के विस्तार से धार्मिक, सांस्कृतिक एवं इको पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल से प्रदेश में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (खंडवा), खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, असीरगढ़ किला और रीवा किला जैसे विभिन्न आकर्षणों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।

मध्यप्रदेश सहित महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश के 7 जिले होंगे कवर

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री-मंडल ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी लागत 7 हजार 927 करोड़ रुपये है। इनमें जलगांव-मनमाड चौथी लाइन (160 किमी), भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किमी) तथा प्रयागराज (इरादतगंज) मानिकपुर तीसरी लाइन (84 किमी) शामिल हैं। ये परियोजनाएँ 3 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 7 जिलों को कवर करेंगी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 639 किलोमीटर की वृद्धि होगी। निर्माण अवधि के दौरान लगभग एक लाख मानव-दिनों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। इससे कोयला परिवहन और यात्री ट्रेनों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और मालगाड़ी के यात्रा समय में कमी करने में भी मदद मिलेगी। स्वीकृत परियोजना खंडवा और चित्रकूट जैसे 2 आकांक्षी जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, जिससे लगभग एक हजार 319 गांवों और लगभग 38 लाख आबादी को सेवा मिलेगी। मुंबई-प्रयागराज-वाराणसी रूट पर अतिरिक्त यात्री ट्रेनों के संचालन को सक्षम करके कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। नासिक (त्र्यंबकेश्वर) और वाराणसी (काशी विश्वनाथ) के ज्योतिर्लिंग के साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। अजंता और एलोरा गुफाएँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, देवगिरी किला, यावल वन्यजीव अभयारण्य, केवटी फॉल्स और पुरवा फॉल्स आदि जैसे विभिन्न आकर्षणों तक बेहतर पहुँच के माध्यम से प्रकृति प्रेमियों और इतिहास में रूचि रखने वाले पर्यटकों को भी सुविधा होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

सप्ताह में 4 दिन रहेगी भोपाल और रीवा फ्लाइट

सुबह 8.15 बजे भोपाल से उड़ेगी, 2 घंटे में रीवा पहुंचेंगी; दोपहर में ही लौटेगी

भोपाल। भोपाल से रीवा के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट उड़ेगी। प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सुबह 8.15 बजे भोपाल से फ्लाइट टेक ऑफ यानी, उड़ान भरेगी, जबकि 2 घंटे में सुबह 10.20 बजे रीवा लैंड करेगी। दोपहर में ही यह फ्लाइट वापस भोपाल लौट जाएगी। अभी पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा के तहत सप्ताह में 6 दिन उड़ान जरूर भरी जा रही है, लेकिन प्लेन सिर्फ छह सीटर है। वहीं, किराया भी अधिक है। इसलिए पूरे यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। अब नियमित फ्लाइट शुरू की गई है। मंगलवार सुबह डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल से रीवा एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट सेवा की शुरुआत करते हुए यात्रियों को बोर्डिंग पास सौंपे। डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि, रीवा एयरपोर्ट से भोपाल की सीधी कनेक्टिविटी विंध्य क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह सेवा क्षेत्र के नागरिकों

के लिए समय की बचत के साथ-साथ सुविधाजनक यात्रा का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा, यह हवाई सेवा रीवा को राज्य और देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इससे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही यह क्षेत्र के सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य को देश-विदेश के पर्यटकों तक पहुंचाने में भी सहायक होगी। डिप्टी सीएम शुक्ल ने भोपाल के राजा भोज अंतरराष्ट्रीय विमानतल पर 'फ्लाई बिग' कंपनी के टिकट काउंटर का उद्घाटन भी किया। सांसद शर्मा, एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी, 'फ्लाई बिग' कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। रीवा और भोपाल के बीच 'Fly Big' कंपनी की उड़ान सेवा सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध रहेगी। भोपाल से रीवा की उड़ान (फ्लाइट नंबर S9-514) मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और शुक्रवार को उपलब्ध होगी। भोपाल एयरपोर्ट से फ्लाइट सुबह 8.15 बजे प्रस्थान करेगी और रीवा एयरपोर्ट पर सुबह 10.20 बजे पहुंचेगी। रीवा से भोपाल की उड़ान (फ्लाइट नंबर S9-515) सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और गुरुवार को संचालित होगी। रीवा एयरपोर्ट से यह फ्लाइट दोपहर 1.40 बजे प्रस्थान करेगी और भोपाल एयरपोर्ट पर 3.45 बजे पहुंचेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर अवस्थी ने बताया, रीवा और भोपाल के बीच निर्धारित उड़ान सेवाएं (शेड्यूअल्ड फ्लाइट सर्विस) आज से शुरू हो गई हैं, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। कुछ सीटें 999 रुपए में उड़ान योजना अंतर्गत आरक्षित हैं, जबकि शेष सीटों की कीमतें डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल के तहत तय की जाएंगी। यह पहल अधिकतम लोगों को सस्ती और सुविधाजनक हवाई यात्रा का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। यह सेवा क्षेत्र के यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।